सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

यदि आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो इसे एक लक्ष्य से बांधें न कि लोगों या चीजों से !

वर्ष 01, अंक 238, नई दिल्ली

गुरुवार, 09 नवम्बर 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड इन वाहनों की दिल्ली में एंट्री बैन

प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार का एक और बड़ा फैसला

संजय बाटला

जहरीली हवा और आसमान में धुंध से दिल्ली के लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली समेत अन्य सरकारें एक के बाद एक कदम उठा रही हैं। अब दिल्ली सरकार ने दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड एप आधारित टैक्सी को राजधानी में एंट्री पर बैन लगाने का फैसला किया है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने ये एलान किया है।

नई दिल्ली। राजधानी में प्रदूषण का स्तर हर रोज भयानक रूप ले रहा है। जहरीली हवा और आसमान में धुंध से दिल्ली के लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली समेत अन्य सरकारें एक के बाद एक कदम उठा रही हैं।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल यानी मंगलवार को दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आज बुधवार को सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाई। बैठक के बाद के बाद गोपाल राय ने कहा कि पहले ऑड-ईवेन के प्रभावशीलता का आंकलन किया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही क्रियान्वयन होगा

दूसरे राज्यों की एप आधारित टैक्सी पर बैन

वहीं दिल्ली सरकार ने दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड एप आधारित टैक्सी को राजधानी में एंट्री पर बैन लगाने का फैसला किया है। बुधवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉफ्रेंस में बताया कि कोर्ट ने दिल्ली के लिए कहा है कि एप आधारित रजिस्ट्रेशन वाली बाहर की टैक्सियों को बैन लगाया जाए।

ट्रांसपोर्ट विभाग को बैन लगाने का निर्देश

दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग को निर्देश दिया गया है कि एप आधारित बाहर से आने वाली टैक्सियों पर बैन लगाया जाए। मतलब दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ओला-उबर सहित अन्य ऐप आधारित टैक्सियों की दिल्ली में एंट्री पर प्रतिबंध लग गया है। अब सिर्फ DL नंबर वाली ऐप आधारित टैक्सियां दिल्ली में चलेंगी।

दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-4 लागू

इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप का चौथा चरण का लागू कर दिया गया। ग्रेप के चौथे चरण के कारण दिल्ली में BS-III पेट्रोल वाहनों और BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध है। साथ ही LNG, CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों, आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छोड़कर अन्य ट्रकों की दिल्ली में एंट्री बैन है।

दिल्ली के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश

खास बात है कि दिल्ली 10 वीं और 12 वीं को छोड़कर अन्य सभी स्कूल 10 नवंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया था। अब सरकार ने छात्रहित को देखते हुए एक और बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के सभी स्कूल शीतकालीन अवकाश के तहत 9 नवंबर 2023 से 18 नवंबर 2023 तक बंद रहेंगे।

निर्माण-कार्यों पर भी प्रतिबंध

दिल्ली में इलेक्ट्रिक, सीएनजी, बीएस-6 डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर एलसीवी वाहनों को छोड़कर दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और पावर ट्रांसमिशन पाइपलाइनों पर विध्वंस कार्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर भी प्रतिबंध रहेगा।

advertisement Tariff
w.ef. 1st January 2023

परिवहन विशेष
दिल्ली, एनसीआर से प्रसारित लोकप्रिय साप्ताहिक हिन्दी समाचार पत्र

in Rs. / Sq. Cm.

	Basic	3rd Page	Back Page	Front Page Semi Solus	Font Page Solus
Delhi Aur Delhi	BW - Colour	Colour	Colour	Colour	Colour
Delhi	100*	200*	250*	300	300

Special Instructions:-
- Innovation on any page will be accepted at a premium of 100% on applicable card rate.
- Any specified position will be accepted at a premium of 25% on applicable card rate.
- B/W advertisement on page 3/Back will charged at colour rate.
- Classified display advertisement will be charged on basic display rate.
- Pointers 4x4 sq. C. or 5x4 sq. cm. will be charged as per card rate.
- box reply charges (each box) will be charged Rs. 150/-
- Political advertisement - as applicable.

परिवहन विशेष में विज्ञापन के लिए ऑनलाईन भुगतान सीधे बैंक खाते/फ़ोन पे पर कर सकते हैं और विज्ञापन के मैटर के साथ ऑनलाईन भुगतान की रसीद व्हाट्सऐप नंबर 09212122095 या newstransportvishesh@gmail.com पर भेज सकते है। भुगतान करने के लिए *NEFT / IMPS / RTGS*
Account Name:-Transport Vishesh Limited
IFSC CODE :- INDB0001396
Cur Account no :- 259212122095
या Phone pay :- 9212122095

अनोखा रियासी रेलवे स्टेशनः

कटरा-बनिहाल परियोजना, ब्रिज 39, दो प्लेटफार्म, जम्मू और कश्मीर

संजय बाटला

नई दिल्ली। कटरा-बनिहाल रेल परियोजना के तहत रियासी में एक अनोखा रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। रियासी रेलवे स्टेशन दो रेलवे सुरंगों के बीच स्थित है और इसकी विशिष्ट विशेषता यह है कि इसे ब्रिज नंबर 39 पर बनाया जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन में दो प्लेटफार्म होंगे, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा रेलवे ब्रिज पर स्थित होगा। रियासी रेलवे स्टेशन की योजना जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के लिए बनाई गई है, जिसका स्टेशन कोड REASI है। यह रियासी शहर की सेवा करेगा। रियासी जिला त्रिकुटा पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है, जो पीर पंगाल के दक्षिणी किनारे पर स्थित है।

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और दिल्ली सरकार के प्रदूषण के नाम पर दोहरा रवैया और भेदभाव करने के खिलाफ दिल्ली एनसीआर के टैक्सी और टेम्पो ट्रेवलर द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और दिल्ली सरकार के प्रदूषण के नाम पर दोहरा रवैया और भेदभाव करने के खिलाफ दिल्ली एनसीआर के टैक्सी और टेम्पो ट्रेवलर के मालिक, दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में CAQM और दिल्ली सरकार के खिलाफ 9 नवम्बर को जंतर मंतर पर भारी धरना प्रदर्शन करने जा रहें हैं.

यें प्रदर्शन प्रदूषण की आड़ में डीजल BS 3 और 4 टैक्सी और टेम्पो ट्रैवेलर (LMV 4 पहिये) को रोड पर ना चलने देने के खिलाफ हैं

मुख्य मांगे :-

1:- डीजल BS 3 और 4 टैक्सी और टेम्पो ट्रेवलर (LMV 4 पहिये) को रोड पर चलने की इज्जाजत तूरंत दी जाए.

2:- डीजल BS 3 और 4 टैक्सी और टेम्पो ट्रेवलर (LMV 4 पहिये) ग्रेडड रिस्पांस एक्शन प्लान फॉर एनसीआर के ग्रेप स्टेज से हमेशा के लिए बाहर किया जाए.

3:- 1 नवम्बर 2023 के बाद हमारी जितनी टूरिस्ट टैक्सी बसों और टेम्पो ट्रैवेलर के चालान हुए हैं वो सारे चालान केन्सिल किये जाए.

4:- हमारी BS 3 और 4 की जितनी टूरिस्ट गाड़ियाँ हैं उनकी जितनी लाइफ हैं उन्हें उतना चलने दिया जाए.

5. प्रदूषण पराली जलाने से, कंस्ट्रक्शन की धुल मिट्टी से होता हैं, इनको कंट्रोल किया जाए.

ट्रंसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना हैं की जब कमिसन फॉर एयर क्वाल्टी मैनेजमेंट आल इंडिया टूरिस्ट परमिट की डीजल BS 4 बसों और टेम्पो ट्रेवलर (6 पहिये) को चलने की इज्जाजत दें दी हैं बल्कि इन गाड़ियों को ग्रेडड रिस्पांस एक्शन प्लान फॉर एनसीआर से ग्रेप सिस्टम से भी बाहर रखा हैं मतलब कभी भी AQI कितना भी हो यें गाड़ियाँ चलती रहेंगी क्योंकि यें देशी विदेशी पर्यटको को दिल्ली से बाहर घुमाने ले जाती हैं. इसके लिए भी हमने लगातार प्रदर्शन किये थे और हमरे धरने प्रदर्शन की वजह से बाद में कमिसन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने आल इंडिया टूरिस्ट परमिट की BS 4 बसों और टेम्पो ट्रेवलर को दिल्ली एनसीआर में चलने और पर्यटको को बाहर दुसरे राज्यों में घुमाने के लिए इज्जाजत दी.

संजय सम्राट का कहना हैं की जब डीजल BS 4 बसें और टेम्पो ट्रेवलर(6पहिये)की चल सकती हैं तो हमारी गाड़ियों को क्यों रोका गया हैं ? क्या कमिसन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट गाड़ियों के पाहियों के हिसाब से प्रदूषण का पैमाना बना रहा हैं ?

यें करोडो लोगों की रोजी रोटी का सवाल हैं. अगर इन्होने हमारी गाड़ियों को चलने की इज्जाजत नहीं दी तो दिल्ली एनसीआर के ट्रांसपोर्टरस काली दिवाली बनाएंगे. क्योकि ट्रांसपोर्टर्स पर ना तो ड्राइवर की सैलरी देने के पैसे हैं और ना हीं घर मे रोजी रोटी चलाने के.

और दिल्ली सरकार और CAQM प्रदूषण की आड़ में BS 6 डीजल गाड़ियों को और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बिकवाने का काम कर रहें हैं ऐसी पूरी संभावना हमें लग रही हैं ?

क्योंकि BS 6 डीजल गाड़ियों को और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलने की इज्जाजत इन्होने दी हुई हैं क्योंकि इन्हे लगता हैं की यें गाड़ियाँ ऑक्सीजन दें रही हैं ?

CAQM और दिल्ली सरकार के तुगलकी फरमान से दिल्ली एनसीआर के लोग हीं नहीं पूरे भारत के लोग परेशान हैं जो दिल्ली में BS 4 डीजल प्राइवेट कारे और BS 3 पेट्रोल कारे लेकर आ रहें हैं उनसे 20 हजार रुपए चालान के नाम लिए जा रहें हैं, इतना जुर्माना तो विदेशी शासको ने भी कभी भारत की जनता पर नहीं लगाया जितना दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी ने लगवा दिया हैं.

यें भारी जुर्माना इसलिए लगाया हैं जिससे लोग BS 6 या इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने पर मजबूर हो जाए ?

कहीं ना कहीं इसमें कार और बसें बनाने वाली कम्पनियो से मिलीभगत होने की भी संभवाना नजर आती हैं ?

आक्रोश धरना प्रदर्शन

प्रदूषण की आड़ में डीजल BS 3 और 4 टैक्सी और टेम्पो ट्रैवेलर (LMV 4 पहिये) को रोड पर ना चलने देने के खिलाफ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और दिल्ली सरकार के खिलाफ

विशाल धरना प्रदर्शन

हमारी मांगे :-

1:- डीजल BS 3 और 4 टैक्सी और टेम्पो ट्रेवलर (LMV 4 पहिये) को रोड पर चलने की इज्जाजत तूरंत दी जाए.

2:- डीजल BS 3 और 4 टैक्सी और टेम्पो ट्रेवलर (LMV 4 पहिये) ग्रेडड रिस्पांस एक्शन प्लान फॉर एनसीआर के ग्रेप स्टेज से हमेशा के लिए बाहर किया जाए.

3:- 1 नवम्बर 2023 के बाद हमारी जितनी टूरिस्ट टैक्सी बसों और टेम्पो ट्रैवेलर के चालान हुए हैं वो सारे चालान केन्सिल किये जाए.

4:- हमारी BS 3 और 4 की जितनी टूरिस्ट गाड़ियाँ हैं उनकी जितनी लाइफ हैं उन्हें उतना चलने दिया जाए.

5. प्रदूषण पराली जलाने से, कंस्ट्रक्शन की धुल मिट्टी से होता हैं, इनको कंट्रोल किया जाए.

निवेदक :- समस्त दिल्ली एनसीआर के टैक्सी बस और टेम्पो ट्रैवेलर मालिक

वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के रुख का असर

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद केंद्रीय और स्टेट एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। शीर्ष अदालत की स्मॉग टावर को लेकर तल्ख टिप्पणी के बाद कनाट प्लेस स्थित टावर को फिर से चालू कर दिया है। इस टावर का निर्माण साल 2021 में शीर्ष अदालत के आदेश पर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने स्मॉग टॉवर की मरम्मत करने का निर्देश सरकार को दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्मॉग टावर का चालू करना जरूरी है। दरअसल, वायू प्रदूषण पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद

दिल्ली की आम आदमी पार्टी के सयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने फिर अपनी गलतियों को ना मानते हुए राजनीतिक रंग देने लगें और गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए

जनता को गुमराह करने में लग गए और सारा इल्जाम दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष और आईएएस अश्वनी कुमार पर लगाते हुए दिखे और बोले आईएएस अश्विनी कुमार ने ने एकतरफा फैसला लेते हुए

कनाट प्लेस स्थित स्मॉग टावर को बंद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इसे चालू करने का निर्देश दिया था। उसके बाद एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की एक टीम को स्मॉग टावर के निरीक्षण के लिए भेजा गया है, जो सुनिश्चित करेगी कि टावर फिर से काम करे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हाल ही में मीडिया को जानकारी दी थी केंद्र के इशारे पर डीपीसीसी अध्यक्ष अश्वनी कुमार ने स्मॉग टावर को बंद कर दिया है। इतना ही नहीं डीपीसीसी ने आईआईटी-बॉम्बे और दूसरी एजेंसियों को दी जाने वाली धन राशि पर सरकार को सूचित किए बिना रोक लगा दी थी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने 23 अगस्त, 2021 को कनॉट प्लेस में 24 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्मॉग टॉवर का उद्घाटन किया था। दिल्ली सरकार ने कनॉट प्लेस में लगे स्मॉग टावर का निरीक्षण करने के लिए बुधवार को एक टीम भेजी थी। मैकेनिकल टीम बुधवार सुबह से इसे चालू के काम में जुटी थी और इस टीम ने स्मॉग टावर को फिर से चालू कर दिया है।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020) , एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

सौंदर्य और साहस थी रानी की पहचान, 29 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी आजादी की आखिरी जंग

18 जून 1858 की सुबह लक्ष्मीबाई अपनी आखिरी जंग के लिए तैयार हुई और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थीं। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर लोगों में अलग-अलग मत है लेकिन लॉर्ड कैनिंग की रिपोर्ट को विश्वसनीय माना जाता है।

बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो, झांसी वाली रानी थी', हम सबका बचपन इन्हीं कविताओं को पढ़ते और वीरांगनाओं की गाथाएं सुनते हुए बीता है। ऐसे में आज हम बात करेंगे असाधारण व्यक्तित्व की धनी और अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति रहीं झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की। जिन्होंने अंतिम क्षण तक अंग्रेजों के खिलाफ कभी न हार मानने वाला युद्ध लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुईं। जीते जी उन्होंने अंग्रेजों को अपने गढ़ पर कब्जा नहीं करने दिया था।

शादी के बाद मिला रानी लक्ष्मीबाई नाम

रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर, 1828 में बनारस के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से मनु बुलाया जाता था। 1842 में मनु की शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवलेकर से कर दी गई। शादी के बाद मणिकर्णिका का नाम लक्ष्मीबाई पड़ा था।

पति और बेटे के मौत के बाद संभाला साम्राज्य

विवाह के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो केवल चार महीने ही जीवित रह पाया। इसके बाद मानो लक्ष्मीबाई की किस्मत ही बदलने लगी। दरअसल, शादी के 11 साल बाद महाराजा का भी निधन हो गया था। पति और बेटे को खोने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ठान ली थी कि वे अपने साम्राज्य और साम्राज्य के लोगों की रक्षा करेंगी।

झांसी पर कब्जा करने की फिराक में रहे अंग्रेज

झांसी के महाराजा की मृत्यु के समय भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का वायसराय डलहौजी थी, उसको लगा कि यह झांसी पर कब्जा करने का सबसे बेहतर समय है, क्योंकि वहां रक्षा करने के लिए और जंग लड़ने के लिए कोई नहीं है। इसके बाद उसने रानी लक्ष्मीबाई से बातचीत का दौर शुरू किया।

दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना अंग्रेजों को अस्वीकार

लगातार अंग्रेजी सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई को यह समझ आ गया था कि इस समय अंग्रेजी हुकूमत की नजर झांसी पर है, तो उन्होंने महाराजा गंगाधर के चचेरे भाई दामोदर को अपना दत्तक पुत्र बना लिया।

रानी लक्ष्मीबाई के सामने रखी पेशकश

अंग्रेजी हुकूमत ने दत्तक पुत्र दामोदर को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और लक्ष्मीबाई के खिलाफ हो गए। अंग्रेजी हुकूमत ने झांसी की रानी को सालाना 60000 रुपये पेंशन लेने और झांसी का किला उनके हवाले करने को कहा।

अंग्रेजों के खिलाफ बनाई बागियों की फौज

रानी लक्ष्मीबाई को समझ आ गया था कि अंग्रेज अब बल प्रयोग करके उनके साम्राज्य पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए गुलाम गौस खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, काशी बाई, लाला भाई बख्शी, मोती बाई, दीवान रघुनाथ सिंह और दीवान जवाहर सिंह के साथ मिलकर 14000 बागियों की एक बड़ी फौज तैयार कर ली। इस फौज में शामिल काशी बाई बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी।

रानी ने अंग्रेजों के सामने झुकने से किया इनकार

रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से भिड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपने मन में ठान ली थी कि किसी भी परिस्थिति में वो अपनी झांसी अंग्रेजी हुकूमत को नहीं सौपेंगी। माना जाता है कि अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई से निहत्थे मिलने को कहा था, ताकि वे बातचीत कर सके, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को भरोसा नहीं हो रहा था। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से मिलने से इनकार कर दिया।

दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर मैदान-ए-जंग में उतरी मर्दानी

23 मार्च, 1858 को ब्रिटिश फौजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया और 30 मार्च को भारी बमबारी की मदद से अंग्रेज किले की दीवार में सेंध लगाने में सफल हो गए। इसके बाद 17 जून, 1858 को रानी लक्ष्मीबाई अपनी आखिरी जंग के लिए निकली। हालांकि, इस दौरान उन्हें पता नहीं था कि यह रात उनकी आखिरी रात होगी। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई अपने पीठ पर अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर जंग के लिए निकल गई। इस दौरान उनकी और अंग्रेजों के साथ काफी जंग हुई।

रानी की मौत को लेकर कई मत

दरअसल, रानी लक्ष्मीबाई के मौत को लेकर काफी असमंजस बना रहता है, लेकिन फिल भी लॉर्ड कैनिंग की रिपोर्ट पर सबसे ज्यादा लोग एकमत होते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक, रानी को एक सैनिक ने पीछे से गोली मारी, इसके बाद जब वह अपने घोड़े को मोड़ती है और उस सैनिक पर गोली चलाती हैं, लेकिन वो बच जाता है। इसके बाद वह सैनिक अपनी तलवार से रानी लक्ष्मीबाई की हत्या कर देता है।

रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से भिड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपने मन में ठान ली थी कि किसी भी परिस्थिति में वो अपनी झांसी अंग्रेजी हुकूमत को नहीं सौपेंगी। माना जाता है कि अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई से निहत्थे मिलने को कहा था, ताकि वे बातचीत कर सके, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को भरोसा नहीं हो रहा था। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से मिलने से इनकार कर दिया।

शौक को बनाया बिजनेस... यह महिला कपड़ों को दे रही नया लुक, खूब आ रहे ऑर्डर

ओम प्रकाश निरंजन/कोडरमा. बचपन के शौक को बिजनेस में बदलकर कई लोग आज आत्मनिर्भर हो रहे हैं. झुमरी तिलैया के गौरी शंकर मोहल्ला रोड निवासी रेणु बडगवे ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया. रेणु वर्तमान में अपने शौक को बिजनेस में बदलकर घर से बेहतर कमाई कर रही हैं.

रेणु ने बताया कि बचपन में उन्होंने अपनी नानी से सिलाई कढ़ाई सीखी थी. शादी के बाद घर गृहस्थी में व्यस्तता के कारण उनका यह शौक छूट गया था. इसके बाद वर्ष 2018 में वह नए घर में शिफ्ट हुई, तब तक बच्चे भी बड़े हो चुके थे. इसके बाद खाली समय में उन्होंने दोबारा से सिलाई और कढ़ाई के अपने शौक को शुरू किया.

कपड़ों पर डिज़ाइन देखकर मिलने लगे ऑर्डर

रेणु ने बताया कि शुरुआती दौर में वह सिर्फ अपने लिए कपड़ों पर आकर्षक डिजाइन तैयार करती थीं. उनके कपड़ों पर आकर्षक डिजाइन देखकर आसपास की महिलाएं काफी पसंद करते हुए प्रभावित होने लगीं. इसके बाद उन्हें मोहल्ले की महिलाओं के द्वारा कपड़ों पर डिजाइन के ऑर्डर मिलने लगे. बताया कि घर से वह आर. फैशन के नाम से बुटीक का संचालन कर रही हैं, जिसमें डिजाइन किए हुए कुर्ती, दुपट्टा, साड़ी, टॉप, लहंगा, लेगिंस महिलाओं को 500 से लेकर 1400 रुपए तक के रेंज में उपलब्ध कराती हैं.

अब पति से नहीं लेने पड़ते पैसे

रेणु ने बताया कि पहले कपड़ों के लिए पति से पैसा लेती थीं, अब घर में संचालित बुटीक से वह आत्मनिर्भर हो चुकी हैं. बुटीक से अपने और बच्चों के कपड़ों का खर्च निकाल लेती हैं. बताया कि लोगों की डिमांड को देखते हुए उनका प्रयास बुटीक को बड़ा रूप देना है. उनके पति दवा के थोक कारोबार से जुड़े हैं.

बाजार का नहीं लगाना पड़ता चक्कर

बुटीक में कपड़े लेने पहुंची विद्यापुरी निवासी प्रतिमा भदानी ने बताया कि घर से नजदीक बुटीक होने पर उन्हें कपड़े लेने में आसानी होती है. यहां उन्हें लेटेस्ट ट्रेंडिंग कपड़े आकर्षक डिजाइन के साथ आसानी से मिल जाते हैं. उन्हें बाजार का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है.

गर्भ में पल रहे बच्चे के फेफड़े भी खराब कर सकती है जहरीली हवा ! प्रेग्नेंट महिलाएं तुरंत करें 5 काम, वरना...

एयर पॉल्यूशन कई जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकता है.एयर पॉल्यूशन कई जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकता है.

खराब एयर क्वालिटी प्रेग्नेंट महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है. जहरीली हवा की वजह से बच्चों को जन्म से ही अस्थमा समेत कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. दिल्ली-एनसीआर में इस वक्त हवा बेहद जहरीली है, जो प्रेग्नेंट महिलाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है. इससे बचने की जरूरत है.

दिल्ली-एनसीआर में हवा की क्वालिटी बेहद खराब हो चुकी है. कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 500 और 600 के पार पहुंच गया है, जो बेहद गंभीर स्तर है. अगले कुछ सप्ताह तक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत आसपास के शहरों की हवा जहरीली रहने की आशंका है. हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि इतना ज्यादा वायु प्रदूषण लोगों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है और आने वाले दिनों में अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ सकती है. जानकारों की मानें तो एयर पॉल्यूशन प्रेग्नेंट महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अत्यधिक घातक हो सकता है. ऐसे में गर्भवती महिलाओं को जहरीली हवा से खुद को हर हाल में बचाना होगा. आज एक्सपर्ट से जानेंगे कि खराब हवा कैसे प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों को प्रभावित कर रही है. साथ ही यह भी जानेंगे कि इस दमघोंटू हवा से किस तरह बचाव किया जा सकता है.

नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित फोर्टिस ला फेम हॉस्पिटल की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. त्रिपत चौधरी के मुताबिक एयर पॉल्यूशन प्रेग्नेंट महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बेहद खतरनाक होता है. प्रेग्नेंसी भ्रूण के विकास की अवधि होती है और इस दौरान वह पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होता है. प्रेग्नेंसी से लेकर जन्म के 2 वर्ष तक एयर पॉल्यूशन का असर बच्चे पर बुरी तरह पड़ता है. अगर प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाएं जहरीली हवा के संपर्क में आएंगी, तो गर्भ में बच रहे बच्चे के फेफड़ों की फंक्शनिंग में कमी हो सकती है और जन्म से ही सांस संबंधी बीमारी व अस्थमा की समस्या पैदा हो सकती है. वायु प्रदूषण की वजह से बच्चे का वजन कम हो सकता है और उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है. एयर पॉल्यूशन भ्रूण के फेफड़ों के विकास को नुकसान पहुंचाता है. गर्भावस्था के दौरान वायु प्रदूषण में रहने से गर्भ में पल रहे बच्चों का ऑर्गन डेवलपमेंट बुरी तरह प्रभावित होता है और जन्म से ही कई परेशानियां हो सकती हैं. गर्भवती महिलाओं के श्वसन तंत्र को भी प्रदूषण से गंभीर नुकसान होता है.

प्रेग्नेंट महिलाएं किस तरह करें बचाव ?

डॉ. त्रिपत चौधरी कहती हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं को इन दिनों सुबह-सुबह बाहर नहीं निकलना चाहिए. जब भी बाहर निकलें, तब N-95 मास्क का इस्तेमाल करें. गर्भावस्था में महिलाओं को अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर रखना चाहिए. पॉल्यूशन के दौरान स्मोकिंग करना बेहद खतरनाक हो सकता है और इससे फेफड़ों को पर डबल अटैक हो सकता है. ऐसे में स्मोकिंग से पूरी तरह दूरी बनाने में ही फायदा है. फेफड़ों को मजबूत रखने वाली एक्सरसाइज और योगासन करना भी फायदेमंद साबित हो सकता है. अगर संभव हो तो घर के अंदर एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल करें.

शिशुओं के लिए भी पॉल्यूशन खतरनाक

फोर्टिस ला फेम के नियोनेटोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. अवधेश आहूजा के अनुसार जहरीली हवा नवजात शिशुओं की सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचाती है. नवजात शिशु एक वयस्क की तुलना में 2-3 गुना तेज सांस लेते हैं. प्रदूषित हवा सीधे उनके फेफड़ों में जाकर इन्फेक्शन पैदा करती है. इन दिनों हॉस्पिटल में तमाम बच्चे खांसी, जुकाम, तेज सांस चलना, आंखों से पानी आना, आंखें लाल होना और दमा जैसी की शिकायत लेकर आ रहे हैं. इन रोगों से ग्रस्त बच्चों की तादाद पॉल्यूशन बढ़ने के बाद काफ़ी बढ़ गई है. आने वाले दिनों में लोगों को बच्चों का विशेष खयाल रखना होगा.

छोटे बच्चों का ऐसे रखें खास खयाल

डॉ. अवधेश आहूजा कहते हैं कि जहरीली हवा से बचने के लिए शिशुओं और बच्चों को घर के अंदर ही ज़्यादा रखें. बाहर की हवा में खेलना दौड़ना कम करें, तो बेहतर होगा. नियमित टीकाकरण जरूर करवाएं. इससे कई जानलेवा बीमारियों से बचा जा सकता है. खांसी-जुकाम या सांस में परेशानी होने जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. घर में धूप, अगरबत्ती दूसरे कमरे में करें जहां शिशु ना हों. कालीन और पर्दों में जहां धूल जमी हो, तो उसका प्रयोग न करें. घर में अगर किसी को सर्दी या खांसी हो, तो नवजात शिशु से दूर रहें या हमेशा मास्क लगाकर रखें. केवल टीकाकरण के समय ही शिशु को घर से बाहर ले जाएं.

दिल्ली में केजरीवाल ने 18 तक स्कूल किए बंद

आरएमडी के अनुमान के मद्देनजर ही 2023-24 के सत्र में सर्दियों की छुट्टियों को पहले करने का आदेश दिया

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली।एसडी सेठी। राजधानी दिल्ली के सभी स्कूलों में विंटर ब्रेक के तहत छुट्टियो का ऐलान कर दिया है। अब सभी स्कूल 9 से 18 नवंबर तक बंद रहेगें। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि प्रदूषण की लगातार बढती रफ्तार के मद्देनजर स्ब्रेकूल ब्रेक में बदलाव कर दिया गया है। वहीं एक अहम फैंसले में दूसरे राज्यों से दिल्ली में आने वाले ऐप आधारित कैब्स पर भी रोक लगा दी है।

बता दें कि इससे पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 10 नवंबर तक स्कूलों को बंद रखने या ऑनलाइन क्लास चलाने का फरमान जारी किया था। इन सारी तिगडम बाजी के बावजूद वायु गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। जबकि स्कूल 18 नवंबर तक बंद रहेगें ,जबकि 19 को रविवार है। इसका मतलब अब स्कूल 20 नवंबर को खुलेंगे। इस बावत शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता के हस्ताक्षर से जारी आदेश में 'गंभीर एक्यूआई की बढती वजह से लागू ग्रैप-4 को माना है। आरएमडी के अनुमान के मद्देनजर ही 2023-24 के सत्र में सर्दियों की छुट्टियों को पहले करने का आदेश दिया जाता है। अब स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। बच्चे -शिक्षक घर पर रह सकते हैं। 12नवंबर को दिवाली है,इस दौरान दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और अधिक बढने की आशंका है। बता दें कि राजधानी दिल्ली के कई इलाकों का एक्यूआई 400-500 से ज्यादा बना हुआ है। ऐसे में डाक्टरों के मुताबिक हवा में खतरनाक प्रदूषण लेवल के चलते छोटे बच्चों और बुजुर्गो को काफी नुकसान होता है। डाक्टरों ने छोटे बच्चों को बाहर कम निकलने की सलाह दी है।

दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश कराएगी केजरीवाल सरकार, IIT कानपुर ने सौंपा पूरा प्लान

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार पहली बार कृत्रिम बारिश कराएगी। जानकारी के अनुसार 20 नवंबर के आसपास कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। आईआईटी कानपुर ने दिल्ली सरकार को पूरा प्लान सौंप दिया है। अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली सरकार इसके बारे में जानकारी देगी। इस दौरान दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट से कृत्रिम बारिश कराने में केंद्र सरकार का सहयोग दिलाने की गुजारिश करेगी।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार पहली बार कृत्रिम बारिश कराएगी। जानकारी के अनुसार, 20 नवंबर के आसपास कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। आईआईटी कानपुर ने दिल्ली सरकार को पूरा प्लान सौंप दिया है। बता दें कि मंगलवार यानी 07 नवंबर को आईआईटी कानपुर की दिल्ली के मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक हुई थी। अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली सरकार इसके बारे में जानकारी देगी। इस दौरान दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट से कृत्रिम बारिश कराने में केंद्र सरकार का सहयोग दिलाने की गुजारिश करेगी।

प्रदूषण के चलते DU के तीन कॉलेज बंद, सिर्फ ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस; शिक्षकों के लिए आया ये आदेश

दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज मार्निंग और हंसराज कॉलेज की ओर से छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की अधिसूचना जारी की गई है।

प्रदूषण का असर अब दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों पर भी दिखने लगा है। डीयू के तीन कॉलेज जाकिर हुसैन कॉलेज मार्निंग हंसराज कॉलेज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ने ऑफलाइन कक्षाएं बंद रहने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके स्थान पर सभी कक्षाएं ऑनलाइन ही संचालित की जाएगी। शिक्षकों को भी कॉलेज आने या घर से कक्षाएं लेने का विकल्प दिया गया है।

नई दिल्ली। प्रदूषण का असर अब दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों पर भी दिखाई देने लगा है। पहले स्कूली बच्चों को लेकर ही चिंता जताई जा रही थी, लेकिन अब कॉलेज प्रशासन भी सतर्क हो गया है। डीयू के तीन कॉलेजों ने कक्षाएं आनलाइन कर दी है। अन्य कॉलेज विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से अधिसूचना जारी होने का इंतजार कर रहे हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज मार्निंग और हंसराज कॉलेज की ओर से छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि आठ नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक कक्षाएं ऑनलाइन लगेंगी और इसके बाद स्थिति को देखते हुए आगे का निर्णय लिया जाएगा। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में 15 नवंबर तक कक्षाएं ऑनलाइन ही संचालित की जाएगी।

शिक्षकों को भी कॉलेज आने या घर से कक्षाएं लेने का विकल्प दिया गया है। जाकिर हुसैन कॉलेज के छात्र अनमोल ने कहा कि एक्यूआई का स्तर लगातार खतरनाक स्थिति में है। छात्रों को बाहर निकलने में परेशानी हो रही थी। कुछ छात्रों को जुकाम की शिकायत हो गई थी।

प्रदूषण के चलते छात्र हित में निर्णय लेने की मांग

वहीं छात्र संघ के एक पदाधिकारी ने कहा कि हम कॉलेज के अधिकारियों से मांग कर रहे थे कि प्रदूषण को देखते हुए छात्रों के हित में कोई निर्णय लिया जाए। हंसराज कॉलेज के एक प्रोफेसर ने कहा- प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। अब ऑनलाइन कक्षाएं चलाने में कोई समस्या नहीं होती है, इसलिए निर्णय लिया गया है। अगर प्रदूषण का स्तर 14 नवंबर तक यही बना रहता है या हालात और खराब होते हैं तो कक्षाओं को आगे बढ़ा दिया जाएगा।

कॉलेज अपने स्तर पर निर्णय लें: प्रो. रजनी अब्बी

डीयू की प्रॉक्टर प्रो. रजनी अब्बी ने कहा- कॉलेज अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। विश्वविद्यालय इस कक्षाओं को ऑनलाइन चलाने को लेकर कोई विचार नहीं किया है। हालांकि, अगर दिवाली के बाद हालात खराब होते हैं तो कक्षाओं को ऑनलाइन मोड पर चलाने पर विचार किया जाएगा।

डीयू के आदेश का इंतजार कर रहे अन्य कॉलेज

रामजस कॉलेज के एक अधिकारी ने कहा- वे ऑफलाइन कक्षाएं चला रहे हैं। डीयू की ओर से कोई आदेश नहीं मिला है। इस पर हमारी ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। डीयू कोई अधिसूचना जारी करता है, इसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। किरोड़ीमल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. दिनेश खट्टर ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई अधिसूचना जारी होती है, तभी वे कक्षाओं को लेकर निर्णय लेंगे।

50 लाख से ज्यादा के गहने लूटने वाले दो बदमाश गिरफ्तार, दिल्ली-NCR में 3 महीनों में की ताबड़तोड़ 10 लूट की वारदात

दिल्ली में पिस्टल के बल पर दिनदहाड़े ज्वेलरी शोरूम में लूट की ताबड़तोड़ वारदात अंजाम देने वाले दो कुख्यात बदमाशों को मानसरोवर पार्क थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने 50 लाख रुपये से अधिक के सोने के गहने लूटे थे। ध्याना देने वाली बात है कि पकड़े गए बदमाशों ने पिछले तीन माह में दिल्ली-एनसीआर में ज्वेलरी शोरूम समेत लूट की दस वारदात अंजाम दी हैं।

दिल्ली। राजधानी में पिस्टल के बल पर दिनदहाड़े ज्वेलरी शोरूम में लूट की ताबड़तोड़ वारदात अंजाम देने वाले दो कुख्यात बदमाशों को मानसरोवर पार्क थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दो शोरूम से बदमाशों ने 50 लाख रुपये से अधिक के सोने के गहने लूटे थे।

तीन माह में लूट की 10 वारदात

बदमाशों की पहचान ब्रह्मपुरी निवासी खालिद उर्फ इजहार और न्यू सीलमपुर निवासी मोहम्मद फहीम के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से लूट की दो मोटरसाइकिल, एक पिस्टल, छह मोबाइल व अन्य सामान जब्त किया है। पिछले तीन माह में बदमाशों ने दिल्ली-एनसीआर में ज्वेलरी शोरूम समेत लूट की दस वारदात अंजाम दी हैं।

शोरूम से लूट ले गए नकदी और 20 मोबाइल

शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त रोहित मीना ने बताया कि हरदेवपुरी में हनीफ खान मोबाइल शोरूम चलाते हैं। वह 15 अक्टूबर को अपने शोरूम पर बैठे हुए थे। तभी बदमाश आए और पिस्टल के बल पर उनसे नकदी और 20 मोबाइल लूटकर ले गए। मानसरोवर पार्क थाना पुलिस ने प्राथमिकी की।

पुलिस ने खंगाले थे 100 से ज्यादा CCTV कैमरे

थानाध्यक्ष प्रशांत यादव के नेतृत्व में एसआइ जीतपाल, एएसआई जसबीर सिंह, दीपक कुमार, हेड कॉन्स्टेबल अनुज कुमार की टीम बनाई। टीम ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले। एक फुटेज में बदमाश कैद मिले। उसके जरिये पुलिस ने बदमाशों की पहचान की। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। बदमाश दहरादून, मेरठ में अपने ठिकाने लगातार बदल रहे थे।

फहीम पर दर्ज हैं 54 आपराधिक केस

गुप्त सूचना पर पुलिस ने इन्हें जीटी रोड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को जांच में पता चला कि फहीम पर लूट, झपटमारी समेत कई धाराओं में 54 आपराधिक केस पहले से दर्ज हैं। झपटमारी के मामले में वह जून में जेल गया था। अगस्त में जेल से जमानत पर बाहर आया था। वर्ष 2016 में नाबालिग था, तभी से वारदात को अंजाम देता चला आ रहा है। जेल में रहने के दौरान वह कुख्यात बदमाशों के संपर्क में आ गया था।

दिनदहाड़े लूटे थे 40 लाख के गहने

पुलिस को जांच में पता चला कि 23 सितंबर को फहीम ने विजय विहार इलाके में दिनहदाड़े अपने साथियों के साथ मिलकर ज्वेलरी शोरूम से 40 लाख रुपये के गहने लूटे थे। शोरूम के पास किराये पर कमरा लेकर पहले रेकी की थी, फिर वारदात को अंजाम दिया था। एक नवंबर को अपने दो साथियों के साथ मिलकर करावल नगर में ज्वेलर के यहां पर लूट की थी। वहां से भागते वक्त एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल लूटी थी। आंबेडकर इलाके से एक शख्स से पिस्टल के बल पर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल लूटी थी। उत्तर प्रदेश के शामली में पिस्टल के बल पर शख्स को लूटा था।

हिंदुस्तानी भाषा काव्य प्रतिभा सम्मान-2023 संपन्न

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

हिंदुस्तानी भाषा अकादमी की ओर से आईटीओ स्थित एनडी तिवारी सभागार में आयोजित द्वितीय भव्य कार्यक्रम में मेरठ के वरिष्ठ साहित्यकार ब्रज किशोर 'राहगीर' को 'हिंदुस्तानी भाषा काव्य प्रतिभा सम्मान-2023 गुलदस्ता -ए-गजल से नवाजा गया। सम्मान स्वरूप उन्हें शॉल,प्रशस्तिपत्र, प्रतीक चिन्ह पुस्तक 'सांझा गजल संग्रह 'गुलदस्ता-ए-गजल' की प्रति तथा नगद सम्मान राशि भेंट की गई।

इस अवसर पर हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष सुधाकर पाठक ने बताया कि अकादमी भारतीय भाषाओं के संवर्धन के साथ ही स्तरीय साहित्य को प्रोत्साहित करती है।इसी क्रम में साहित्य की गजल विधा के लिए सोशल मीडिया के जरिए देश-विदेश के गजलकारों से उनकी उनकी 3-3 गजलें बतौर प्रविष्टी के आमंत्रित की गई थी। उन गजलों के आधार पर ही 50 सर्वश्रेष्ठ गजलकारों का चयन किया गया। निर्णायक मंडल द्वारा इन 50 गजलकारो में से ही ब्रज राज किशोर 'राहगीर' की गजलों को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। चयन की प्रकिया को पारदर्शी रखा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीमाब सुल्तानपुरी ने की। चीफ गेस्ट देवेन्द्र मांझी, डॉ. केशव मोहन थे। मंच संचालन अकादमी के संजय गरिमा, डॉ.सोनिया अरोडा और विनोद पराशर ने किया।

मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भी एस०सी० / एस०टी० एक्ट 1989 में शामिल किया जाए

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। आल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले आज गालिब अकादमी में ₹सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता हाफिज गुलाम सरवर ने की।

अध्यक्षीय पद से अपना विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमान की बड़ी आबादी इस समय अपनी जानी-माली सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित रहता है। शैक्षिक एवं आर्थिक बदहालियों के बावजूद सुरक्षा₹ ही सबसे बड़ी समस्या रही है और इस इशू पर इस समाज ने इन 75 वर्षों में वोट देने का काम किया है। पालिटिकल पार्टियों ने अपने शासन कालों में राष्ट्रपति, गवर्नर, मंत्री पद जैसे बड़े पदों पर मुसलमानें को जगह दी है लेकिन आम मुसलमानों ने हमेशा उस पार्टी को पावर में रखने की कोशिश की है जो उसे सुरक्षा देने में चम्पयन लगा । आज के बदलते राजनीतिक माहौल में उसे कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता है, अब केवल ₹जुबानी सुरक्षा से काम नहीं चलने वाला है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की बड़ी आबादी यही चाहती है कि उसे भी एस०सी०/ एस०टी० एक्ट (1989) में शामिल किया जाए और जो पार्टी इस मांग को पूरी करेगा उसे ही ये आबादी वोट देने का काम करेगा।

मोर्चा के महामंत्री, शब्बीर मंसूरी ने कहा कि मुसलमानों की बड़ी आबादी आज देश में ₹महासेवक है। पंकचर बनाना, कचड़ा बीनना, चिकेन मटन बनाना, साग-सब्जी बेचना, सिलाई बुनाई, धुनाई, मजूदरी आदि इनकी प्रमुख सेवायें हैं। इस सम्बन्ध में सभी भारतीय एक दूसरे पर आश्रित है जो सादियों से चला आ रहा है। सम्प्रदायिक तनाव या दंगे होने पर इस सिलसिले पर ब्रेक लगता है और समस्त देशवासी इसके भुक्त-भोगी हो जाते है।

मोर्चा के उपाध्यक्ष अब्दुल हकीम हवारी ने कहा कि अत्याचार निवारण एक्ट 1989 बनने से सामाजिक अत्याचार' (Social Voilence) पर बहुत रोक लगा है। इसी कानून में अगर मुसलमानों को शामिल कर दया जाए तो फिर सम्प्रदायिक अत्याचार (Communal Voilance) पर भी रोक लग जाएगा, जो देशहित में भी आवश्यक है।

इस अवसर पर प्रोफ़ेसर रब्बानी (इलाहबाद), अतीकुर रहमान एडवोकेट, डॉ ऍम यु दुआ, चतर सिंह रछौया, इंजीनियर डी सी कपिल, सग़ीर अब्बासी, दिलशाद अली ने भी अपनी बात राखी और सरकार से क़ानूनी सुरक्षा की मांग की।

कांफ्रेंस में यही मांग रही कि केन्द्र सरकार एक अध्यादेश लाकर ₹अत्याचार निवारण एक्ट 1989 में दलितों एवं आदिवासियों के साथ मुसलमानों को भी किसी रूप में शामिल कर दें। ये देशहित एवं समाजहित में बहुत जरूरी है। ये मांग प्रधानमंत्री को रानीतिक शक्ति देने में बड़ा रौल अदा कर सकता है और वे अमर हो जाएंगे।

गुरुग्राम-फरीदाबाद में इन वाहनों के चलने पर लगी रोक

सड़क पर दिखे तो होगी कार्रवाई; हरियाणा सरकार ने लिया फैसला

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार एक के बाद एक कदम उठा रही है। अब हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद में बीएस तीन (पेट्रोल) व बीएस चार (डीजल) श्रेणी के वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अगर रोक के बावजूद इन वाहनों का इस्तेमाल करते पकड़े गए तो चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गुरुग्राम। हरियाणा सरकार राज्य में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गंभीरता से कार्य कर रही हैं। प्रदेश में नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर सरकार ने अनेक कदम उठाए है। इसी क्रम में गुरुग्राम जिला में बीएस तीन (पेट्रोल) व बीएस चार (डीजल) श्रेणी के वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।

डीसी निशांत कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन आयुक्त, हरियाणा द्वारा गुरुग्राम व फरीदाबाद जिला में बीएस तीन (पेट्रोल) व बीएस चार (डीजल) श्रेणी के चार पहिया लाइट मोटर व्हीकल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। जिला में इन आदेशों की पालना गंभीरता से सुनिश्चित की जाएगी।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिला वासियों को भी प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला में अगर कोई इन श्रेणी के वाहनों का प्रयोग करेगा तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 194 (1) के तहत चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला में यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर हो चुके है, जोकि आगामी 30 नवंबर या ग्रैप की स्टेज तीन हटने तक प्रभावी रहेंगे।

आधी रात काफिले संग नोएडा थाने पहुंचा एल्विश, तीन घंटे तक डरते हुए दिए जवाब

सांप के जहर को रेव पार्टियों में सप्लाई करने के आरोप में फंसे Bigg Boss OTT-2 विनर एल्विश यादव आज रात दो बजे अपने सात अधिवक्ताओं के साथ नोएडा के कोतवाली सेक्टर-20 पहुंचा। डीसीपी हरीश चंदर का कहना है कि पुलिस अब दोबारा से उसे पूछताछ के लिए बुलाएगी। इस मामले में उसने अपने ऊपर सभी लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया।

नोएडा। सांप के जहर को रेव पार्टियों में सप्लाई करने के आरोप में फंसे Bigg Boss OTT-2 विनर एल्विश यादव आज रात दो बजे अपने सात अधिवक्ताओं के साथ नोएडा के कोतवाली सेक्टर-20 पहुंचा। कोतवाली सेक्टर-20 पुलिस ने उसे पार्टी और उसके दोस्तों के कनेक्शन के बारे में पूछा। इस दौरान वो काफी डरा हुआ था। हालांकि अधिवक्ताओं की मौजूदगी में उसमें थोड़ी हनक जरूर दिख रही थी। इस मामले में उसने अपने ऊपर सभी लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया।

स्नेक वेनम और सांप के कार्यक्रम के बारे में जानकारी के बारे पूछा बयान दर्ज कराए गए और करीब पांच बजे वो अपने अधिवक्ताओं के साथ वापस चला गया। डीसीपी हरीश चंदर का कहना है कि पुलिस अब दोबारा से उसे पूछताछ के लिए बुलाएगी।

16000 बिजली कर्मियों को मिलेगा दिवाली गिफ्ट, सीधे बैंक खातों में पहुंचेंगे इतने रुपये

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के सी और डी श्रेणी के सभी कर्मचारियों को दिवाली के उपलक्ष्य में टोकन गिफ्ट मिलेगा। प्रबंध निदेशक ने बताया कि बिजली वितरण निगम ने 2000 रुपये का दिवाली टोकन उपहार देने का फैसला किया है। टोकन उपहार का भुगतान कर्मचारियों के सीधे बैंक खातों में किया जाएगा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के सी और डी श्रेणी के सभी कर्मचारियों को दिवाली के उपलक्ष्य में टोकन गिफ्ट मिलेगा। प्रबंध निदेशक अमित खत्री ने बताया कि बिजली वितरण निगम ने 2000 रुपये का दिवाली टोकन उपहार देने का फैसला किया है। टोकन उपहार का भुगतान कर्मचारियों के सीधे बैंक खातों में किया जाएगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के लगभग 16000 कर्मचारियों को यह टोकन गिफ्ट की राशि दी जाएगी। इसमें बिजली निगम के सभी सी और डी श्रेणी के रेगुलर और अनुबंधित, एचकेआरएनएल के माध्यम से लगे हुए कर्मचारी, कान्ट्रेक्ट बेस, पार्ट टाइम, डीसी रेट के सभी आन रोल कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

वित्त निदेशक रतन कुमार वर्मा ने बताया कि इस बारे सभी डीडीओ एवं कार्यकारी अभियंता को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सभी पात्र कर्मचारियों को दिवाली टोकन उपहार का भुगतान दिवाली से पहले ही जारी कर दिया जाए।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाएं छोटे कारीगर

केंद्र सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत छोटे कारीगरों को सस्ती ब्याज दरों पर लोन और निःशुल्क औजार, प्रशिक्षण, मार्केटिंग सपोर्ट, डिजिटल ट्रांजेक्शन का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन सर्टिफिकेट तथा पहचान पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। डीसी निशांत कुमार यादव ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए 13 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। एमएसएमई विभाग की ओर से चलाई जा रही इस योजना में छोटे औजारों का उपयोग करके अपने हाथों से काम करने वाले 18 श्रेणी के दस्तकारों एवं कारीगरों का आर्थिक उत्थान किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि हमारे समाज के कारीगर जैसे लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मोची, नाई, दर्जी, धोबी, बच्चों के लिए खिलौने बनाने वाले, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, मूर्तिकार, शिल्पकार, राज मिस्त्री आदि को बैंक से रियायती दरों पर लोन व व्यवसाय की ट्रेनिंग भी मिलेगी।

फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी प्रदूषण से हालात खराब, कहीं स्कूल बंद तो कहीं चलेंगी ऑनलाइन कक्षाएं

इस योजना के अंतर्गत इन कारीगरों को तीन लाख रुपये तक के सिक्योरिटी रहित लोन दिए जाते हैं। इसमें पहले एक लाख रुपये का और उसकी अदायगी के बाद दो लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा उनके उन्नत कौशल के लिए प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये दैनिक भत्ता, रुपये 15 हजार रुपये तक की टूल किट, डिजिटल ट्रांजेक्शन, सर्टिफिकेट तथा पहचान पत्र प्रदान किए जाते हैं।

योगी राज में विधायिका पर भारी है यूपी की कार्यपालिका

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में अफसरशाही के चलते केवल आम आदमी ही नहीं मंत्री सांसद और विधायक भी परेशान हैं। यह लोकसेवक लम्बे समय से कार्यपालिका के चलते होने वाली अपनी परेशानी शिकायतों के रूप में सामने रखते रहते हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल सख्त शासक हैं। उनकी छवि काफी साथ-सुथरी है। करीब साढ़े छहः साल के शासनकाल में योगी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। यह एक अच्छी बात है। जनता भी ऐसी ही सरकार चाहती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि योगी को छोड़कर यूपी के अन्य सभी राजनेता बेईमान और भ्रष्टाचारी हैं। सभी दलों में अच्छे-बुरे दोनों किस्म के नेता मौजूद हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का भी यही 'मिजाज' है। यहां भी अन्य दलों की तरह दोनों किस्म के नेता देखने को मिलते हैं। मगर बीजेपी आलाकमान को अपने किसी भी नेता पर भरोसा नहीं है। यहां तक की योगी सरकार के मंत्री भी सरकारी मशीनरी के सामने 'पंख कटे' नजर आते हैं। इसकी वजह है कि बीजेपी में सभी नेताओं को एक ही तराजू में तौला जा रहा हैं। कहने को तो उसके तमाम नेता जनप्रतिनिधि होने का भी रूतबा रखते हैं, लेकिन इन्हें पूरी तरह से दंतविहीन बना दिया गया है। यह न तो कभी अपने क्षेत्र में पुलिस उत्पीड़न के शिकार लोगों के पक्ष में थाने जा सकते हैं, न शासन-प्रशासन में बैठे अधिकारी उनकी सुनते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी मशीनरी को आदेश दे रखा है कि यदि कोई बीजेपी नेता उनके पास किसी की सिफारिश लेकर आये तो उसकी बात सुनने की आवश्यता नहीं है, बल्कि अधिकारी अपने विवेक से सही गलत का फैसला लें। यह सब बातें किसी फाइल में तो नहीं कोड की गई हैं, परंतु राजनीति के गलियारों में यह चर्चा आम है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उसके (सपा) सांसद/मंत्री/विधायक आदि जनप्रतिनिधि पुलिस और सरकारी मशीनरी पर दबाव बना लेते थे, वैसा दबाव बीजेपी के जनप्रतिनिधि नहीं बना पाते हैं। होता यह है कि जब भी बीजेपी का कोई नेता किसी सरकारी अधिकारी या पुलिस के पास पहुंचता है तो उसे सीएम योगी का फरमान याद दिला दिया जाता है। या यों कहें उन्हें अपमानित करके वापस भेज दिया जाता है।

हालात यह है कि यूपी सरकार के अधिकारी बीजेपी के किसी भी जनप्रतिनिधि को भाव नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी ऐसे नेताओं से मिलने का टाइम नहीं रहता है। इसको लेकर योगी के पिछले शासन में बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने विधानसभा के अंदर प्रदर्शन भी किया था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की अपने ही जनप्रतिनिधियों से दूरी हमेशा चर्चा में रहती है। यहां तक की दिल्ली भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आज की तारीख में पार्टी के अंदर योगी का कद काफी बढ़ा हुआ है, इसलिए उन्हें कहीं से चुनौती भी नहीं मिलती है। इसी के चलते पीड़ितों व आम लोगों से पुलिसकर्मियों के दुर्व्यवहार के मामले तो आए दिन सामने आते रहते हैं। पुलिस अधिकारियों व कर्मियों द्वारा माननीयों से भी अच्छा व्यवहार न किए जाने की शिकायतें बढ़ रही हैं। कहने को तो सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर कहते मिल जाते हैं कि जनप्रतिनिधियों का पूरा सम्मान किया जाये। इस बार भी योगी द्वारा माननीयों के प्रति शिष्टाचार व अनुमन्य प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसका असर होते नहीं दिख रहा है।

उत्तर प्रदेश में अफसरशाही के चलते केवल आम आदमी ही नहीं मंत्री सांसद और विधायक भी परेशान हैं। यह लोकसेवक लम्बे समय से कार्यपालिका के चलते होने वाली अपनी परेशानी शिकायतों के रूप में सामने रखते रहते हैं। ज्ञातव्य हो, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इंटीग्रेटेड ग्रीवॉन्स रिड्रेसल सिस्टम लागू कर रखा है, जिसे आइजीआरएस पोर्टल के रूप में जाना जाता है। इसमें कोई भी सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत कर सकता है। इस पोर्टल पर पिछले दो वर्षो में आम जनता के अलावा योगी के कई मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने भी कार्यपालिका की शिकायत दर्ज कराके अपनी लाचारी सार्वजनिक की है। जिसमें काफी चौंकाने वाली बाते सामने आई है। इन माननीयों की शिकायत से पता चलता है कि प्रदेश में तमाम अफसर आमजन तो दूर मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बात को भी तवज्जो नहीं देते हैं और उनके सुझाए गए कार्यों को बेहद लेटलतीफी करते हैं। इस बारे में नेता और विधायक कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कभी कोई हल नहीं निकल पाया। गौरतलब हो हाल ही में भी शासन व डीजीपी मुख्यालय द्वारा पुलिसकर्मियों को इसे लेकर निर्देश दिए गये हैं। प्रमुख सचिव, गृह संजय प्रसाद ने सभी पुलिस आयुक्तों, एसएसपी व एसपी को सांसदों व विधानमंडल के सदस्यों के प्रोटोकाल का अनुपालन कराए जाने को कहा हैं। उन्होंने कहा है कि शासन व संसदीय अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रोटोकाल उल्लंघन के मामले लगातार आ रहे हैं। संजय प्रसाद द्वारा कहा गया है कि सभी अधिकारी सांसदों व विधानमंडल के सदस्यों के सीयूजी नंबर अथवा उनके द्वारा नोट कराया गया अन्य मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से अपने मोबाइल में फीड करेंगे तथा काल आने पर उसे रिसीव करेंगे। किसी बैठक में होने अथवा उपलब्ध न होने की स्थिति में काल की जानकारी होने पर प्राथमिकता पर जनप्रतिनिधि को संदेश भेजने के साथ ही काल कर बात करेंगे। जनप्रतिनिधियों द्वारा फोन पर बताए गए प्रकरणों का यथाशीघ्र निस्तारण कराकर उन्हें जानकारी भी देंगे। इसके साथ ही जिले के अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के मोबाइल पर उनके क्षेत्र के माननीय का फोन नंबर फीड कराएंगे। संजय प्रसाद द्वारा यह भी कहा गया है कि जनप्रतिनिधि यदि किसी जनहित से जुड़े कार्यों के संबंध में उनसे (अधिकारी व कर्मचारी) से भेंट करते हैं तो उनका सीट से खड़े होकर यथोचित सम्मान किया जाए.इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों से वार्ता में यदि उनके अनुरोध अथवा सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थ हों तो अधिकारी उसके कारणों से जनप्रतिनिधियों को विनम्रतापूर्वक अवगत कराएंगे। किसी अनुचित आचरण अथवा जानबूझकर की गई गलती को दुराचरण माना जाएगा और कार्रवाई होगी. जिलों में प्रोटोकाल से जुड़े मामलों के लिए हर दो माह में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक किए जाने का निर्देश भी दिया गया है, मगर यह आदेश कितना प्रभावशाली रहेगा, इसको लेकर लोगों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों को भी संदेह है। जबकि लोकतंत्र में जरूरी है कि जनप्रतिनिधियों की आवाज को उसके सरकारी नौकर न केवल सुने बल्कि गंभीरता से भी लें, क्योंकि हर जनप्रतिनिधि गलत नहीं होता है। जनता उसे चुनती है और उसे जनता को जबाव देना होता है। जनता की समस्याओं को सुनना और उसका समाधान जनप्रतिनिधि की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी भी है।

कावासाकी निंजा 500 और Z500 से उठा पर्दा जानिए इंजन से लेकर फीचर्स तक की डिटेल्स

इस बाइक में नए डिजाइन वाले हेडलैंप यूनिट के साथ नेकेड डिजाइन मिलता है। इसमें आक्रामक दिखने वाले एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हैं। बाइक का बाकी हिस्सा निंजा 500 जैसा ही दिखता है।

Kawasaki Ninja 500 और Z500 एक ही हल्के ट्रेलिस फ्रेम पर आधारित हैं। फुली-फेयर्ड निंजा 500 के बारे में बात करें तो ये मोटरसाइकिल लाइन-अप में अन्य निंजा मॉडल से अपने डिजाइन संकेत उधार लेती है। फीचर्स के मामले में बाइक्स में एक एलसीडी डिजिटल क्लस्टर और एक असिस्ट और स्लिपर क्लच मानक के रूप में मिलता है। आइए दोनों बाइक्स के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। Kawasaki ने EICMA2023 में Kawasaki Ninja 500 और Z500 को पेश किया है। नई निंजा 500 और Z500 में समान प्लेटफॉर्म, इंजन और अन्य कंपोनेंट दिए गए हैं। निंजा 500 एक फुली-फेयर्ड बाइक है, जबकि Z500 एक नेकेड स्ट्रीटफाइटर है। ये बाइक्स दो वेरिएंट में उपलब्ध होंगी, इनमें स्टैंडर्ड और एसई शामिल है। दोनों बाइक में तीन-तीन रंग विकल्प भी मिलते हैं। आइए, इनके बारे में जान लेते हैं।

डिजाइन

Kawasaki Ninja 500 और Z500 एक ही हल्के ट्रेलिस फ्रेम पर आधारित हैं। फुली-फेयर्ड निंजा 500 के बारे में बात करें तो, ये मोटरसाइकिल लाइन-अप में अन्य निंजा मॉडल से अपने डिजाइन संकेत उधार लेती है। सामने की तरफ, इसमें एक ट्विन एलईडी हेडलैंप यूनिट है, जिसके बाद फुल फेयरिंग के साथ एक स्कल्पटेड फ्यूल टैंक है।

पीछे की तरफ इसमें आकर्षक एलईडी टेललाइट्स दिए गए हैं। Z500 की बात करें, तो इस बाइक में नए डिजाइन वाले हेडलैंप यूनिट के साथ नेकेड डिजाइन मिलता है। इसमें आक्रामक दिखने वाले एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हैं। बाइक का बाकी हिस्सा निंजा 500 जैसा ही दिखता है।

फीचर्स

फीचर्स के मामले में, बाइक्स में एक एलसीडी डिजिटल क्लस्टर और एक असिस्ट और स्लिपर क्लच मानक के रूप में मिलता है। कंपनी SE (स्पेशल एडिशन) ट्रिम भी पेश कर रही है, जिसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, रेडिएटर स्क्रीन, क्रैश स्लाइडर्स, पिलियन सीट कवर, टैंक पैड प्लस नी ग्रिप पैड और ERGO-FIT हाई सीट के साथ कलर TFT मीटर मिलता है।

इंजन

पावरट्रेन की बात करें तो बाइक्स को नया लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है। कंपनी ने इस इंजन के पावर और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। उम्मीद है कि इन बाइक्स को 45 बीएचपी और 42 एनएम या टॉर्क के पावर आउटपुट के

2024 KTM 990 Duke से उठा पर्दा, जबरदस्त इंजन के साथ इन फीचर्स से लैस है ये लीटर क्लास बाइक

KTM ने EICMA 2023 में All New 990 Duke को पेश कर दिया है। इसका मुकाबला अन्य लीटर-क्लास नेकेड मोटरसाइकिलों से होगा। 2024 KTM 990 Duke को पावर देने वाला एक नया LC8c इंजन है जो यूरो 5+ के अनुरूप है। ये 947 सीसी पैरेलल-ट्विन लिक्विड-कूल्ड इंजन है। KTM 990 Duke को पूरी तरह से नए स्टील ट्यूब फ्रेम के आसपास विकसित किया गया है।

नई दिल्ली। KTM ने EICMA 2023 में All New 990 Duke को पेश कर दिया है। इसका मुकाबला अन्य लीटर-क्लास नेकेड मोटरसाइकिलों से होगा। नई मोटरसाइकिल लाइनअप में 890 DUKE GP से ऊपर होगी। 990 ड्यूक का उत्पादन ऑस्ट्रिया के मैटीघोफेन में केटीएम के मेन प्लांट में किया जाएगा। फिलहाल, KTM की 990 Duke को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की कोई योजना नहीं है। आइए, इसकी सभी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं।

इंजन

2024 KTM 990 Duke को पावर देने वाला एक नया LC8c इंजन है, जो यूरो 5+ के अनुरूप है। ये 947 सीसी, पैरेलल-ट्विन लिक्विड-कूल्ड इंजन है। यह पावरट्रेन 9,500 आरपीएम पर 121 बीएचपी की अधिकतम पावर और 6,750 आरपीएम पर 103 एनएम का पीक टॉर्क आउटपुट देता है।

इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है और राइडर क्विकशिफ्टर का विकल्प भी चुन सकता है।

स्पेसिफिकेशन

KTM 990 Duke को पूरी तरह से नए स्टील ट्यूब फ्रेम के आसपास विकसित किया गया है। सबफ्रेम एक एल्यूमीनियम डाइकास्ट भाग है, जिसमें सीट के नीचे एक एकीकृत एयरबॉक्स और एयर इंटेक होता है। इसके अलावा, स्विंगआर्म भी नया है और ट्रिपल क्लैंप जाली एल्यूमीनियम से बना है। 990 ड्यूक के पहिए 17 इंच के हैं और 1290 सुपर ड्यूक आर से लिए गए हैं, लेकिन दो तरफा स्विंगआर्म को शामिल करने के लिए थोड़ा अपडेट किया गया है। इन्हें मानक के रूप में ब्रिजस्टोन S22 टायर दिए गए हैं।

डायमेंशन

फ्रेम को सामने की ओर 43 मिमी WP एपेक्स ओपन कार्ट्रिज फोर्क्स द्वारा सस्पेंड किया गया है, जिसमें 140 मिमी का ट्रैवल है। ये कम्प्रेशन और रिबाउंड एडजस्टेबल के साथ आता है जिसे फोर्क्स के शीर्ष पर मौजूद क्लिकर्स के माध्यम से किया जा सकता है। पीछे की तरफ, एक WP एपेक्स मोनोशॉक है, जिसे रिबाउंड के लिए 5-क्लिक सेटिंग और मैन्युअल प्रीलोड एडजस्टमेंट के माध्यम से एडजस्ट किया जा सकता है।

EICMA 2023: Suzuki GSX-S1000GX और GSX-8R को किया गया पेश

Suzuki ने EICMA 2023 में GSX-S1000GX और GSX-8R को पेश किया है। GSX-S1000GX सुजुकी की पहली मोटरसाइकिल है जिसमें सुजुकी एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन (SAES) दिया गया है। वहीं GSX-8R है GSX-8S से प्राप्त एक स्पोर्ट्स मॉडल है। इसमें एक अपडेटेड राइडिंग ट्रायंगल फेयरिंग और थोड़ी अलग डिजाइन लैंग्वेज मिलती है। आइए इन दोनों बाइक्स के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। Suzuki ने EICMA 2023 में दो नई मोटरसाइकिलों का अनावरण किया है। इसमें GSX-S1000GX और GSX-8R शामिल हैं। एक GSX-S1000GX कुछ एडवेंचरस एलीमेंट के साथ एक स्पोर्ट टूरर है, जबकि GSX-8R इसका पूरी तरह से फेयर्ड संस्करण है। फिलहाल, निर्माता ने नई मोटरसाइकिलों के भारत लॉन्च के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। आइए, इन दोनों के बारे में जान लेते हैं।

नई GSX-S1000GX में क्या खास?

GSX-S1000GX सुजुकी की पहली मोटरसाइकिल है, जिसमें सुजुकी एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन (SAES) दिया गया है। इस फीचर की मदद से वाहन की गति, सड़क की सतह की स्थिति और ब्रेक के कारण पोजीशन में बदलाव के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से सस्पेंशन डंपिंग और प्रीलोड को कंट्रोल किया जा सकता है।

ये सुजुकी रोड एडेप्टिव स्टेबिलाइजेशन (SRAS) प्रोग्राम के साथ भी आती है, जो असमान सड़क सतहों का पता लगाता है और इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट (IMU) व अन्य सोर्स से डेटा के साथ एसएडीएस को शामिल करके ऑटोमैटिक सस्पेंशन को स्विच करता है।

इंजन

GSX-S1000GX में 999 cc, DOHC, लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जो 150 bhp की अधिकतम पावर और 106 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। ये वही इंजन है, जो कटाना पर भी ड्यूटी कर रहा है। ऑन ड्यूटी गियरबॉक्स 6-स्पीड यूनिट है।

Suzuki GSX-8R की स्पेसिफिकेशन

GSX-8R है GSX-8S से प्राप्त एक स्पोर्ट्स मॉडल है। इसमें एक अपडेटेड राइडिंग ट्रायंगल, एक पूर्ण फेयरिंग और थोड़ी अलग डिजाइन लैंग्वेज मिलती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि पूरी तरह से फेयर्ड मोटरसाइकिलें क्लिप-ऑन हैंडलबार का उपयोग करती हैं, लेकिन जीएसएक्स-8आर के साथ ऐसा नहीं है, यह अभी भी एक ट्यूबलर हैंडलबार का उपयोग कर रहा है।

फेयरिंग जोड़ने के कारण, GSX-8S की तुलना में वजन 6 किलोग्राम बढ़ गया है।

मोटरसाइकिल तीन रंगों - मेटैलिक ट्राइटन ब्लू, मेटैलिक मैट स्वोर्ड सिल्वर और मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2 में बेची जाएगी।

इंजन

इसमें अन्य 800 मॉडलों की तरह ही 776 सीसी, पैरेलल-ट्विन इंजन का उपयोग किया गया है। आधिकारिक पावर और टॉर्क आउटपुट का खुलासा नहीं किया गया है। हालाँकि, अन्य 800 मॉडलों में ये इंजन 83 bhp की अधिकतम पावर और 78 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है।

2024 Royal Enfield Himalayan 10 हजार रुपये में कर सकेंगे बुक, जानिए प्राइस और डिलीवरी की डिटेल्स

2024 Royal Enfield Himalayan की प्री-बुकिंग 10000 रुपये के टोकन पर शुरू हो गई है। इसको गोवा में होने वाले RE Motoverse में लॉन्च किया जाएगा और इसकी डिलीवरी भी 24 नवंबर के बाद शुरू होगी। एडवेंचर टूरर को 43 मिमी यूएसडी फ्रंट फोर्क्स और पीछे 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक के साथ बिल्कुल नए ट्विन-स्पार प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया है।

नई दिल्ली। न्यू जेनरेशन Royal Enfield Himalayan ने EICMA 2023 में अपनी वैश्विक शुरुआत की है। कंपनी ने न केवल नए एडवेंचर टूरर का विवरण दुनिया के साथ साझा किया, बल्कि पेशकश के लिए भारत में अपनी ऑर्डर बुक भी खोल दी है। नई हिमालयन की प्री-बुकिंग 10,000 रुपये के टोकन पर शुरू हो गई है। इसको गोवा में होने वाले RE Motoverse में लॉन्च किया जाएगा और इसकी डिलीवरी भी 24 नवंबर के बाद शुरू होगी।

2024 Royal Enfield Himalayan का इंजन

2024 Royal Enfield Himalayan को कई चीजें पहली बार मिली हैं, जिनमें लिक्विड-कूल्ड इंजन, फोर्ज्ड पिस्टन सहित हल्के कंपोनेंट, ऑल-डिजिटल कंसोल, राइड-बाय-वायर जैसी कई चीजें शामिल हैं। इसको पावर देने के लिए 450 सीसी का नया शेरपा इंजन दिया गया है। ये सिंगल-सिलेंडर इंजन 8,000 आरपीएम पर 39.4 बीएचपी और 5,500 आरपीएम पर 40 एनएम उत्पन्न कर सकता है। मोटर को स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

स्पेसिफिकेशन

एडवेंचर टूरर को 43 मिमी यूएसडी फ्रंट फोर्क्स और पीछे 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक के साथ बिल्कुल नए ट्विन-स्पार प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जबकि ब्रेकिंग परफॉर्मेंस 320 मिमी सिंगल फ्रंट डिस्क और रियर में डुअल-चैनल एबीएस के साथ 270 डिस्क से आती है। ऑफ-रोड पर जाते समय आपको रियर एबीएस मॉड्यूल को बंद करना होगा। साथ ही इसे राइड-बाय-वायर के साथ बाइक में दो राइडिंग मोड्स - इको और परफॉर्मेंस भी मिलते हैं। इसके अलावा, एक बड़ा 17-लीटर फ्यूल टैंक है, जबकि स्टॉक सीट हाइट 825 मिमी तक बढ़ गई है और इसे 845 मिमी तक बढ़ाने का विकल्प है। हिमालयन 450 में 21 इंच का फ्रंट और 17 इंच का रियर स्पोक व्हील है।

फॉरेन यूनिवर्सिटीज की जरूरत क्यों

डा. वरिंदर भाटिया

यूजीसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज के भारतीय कैंपस और यहां उनके परिचालन से जुड़े 'रेग्यूलेशन 2023' लाने जा रही है। इसके पीछे अनेक तर्क दिए जा रहे हैं, जैसे कि इससे ऐसे मेधावी छात्रों को लाभ होगा जो आर्थिक तंगी के कारण प्रसिद्ध विदेशी विश्वविद्यालयों का रुख नहीं कर सकते।

फिर विदेशी विश्वविद्यालयों को यहां आने के लिए प्रोत्साहित करना उच्च शिक्षा में निजी पूंजीवाद की पकड़ को मजबूत करना भी हो सकता है, परंतु इसके बावजूद विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए लाने का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में विविधता लाना भी है, जिसकी जरूरत से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावित कदम से इन विश्वविद्यालयों को अपने घरेलू देशों में धन वापस भेजने में मदद मिलेगी। उन्हें अपने पाठ्यक्रमों की फीस तय करने की स्वायत्तता है, जिसका सीधा मतलब यह है कि पाठ्यक्रम महंगे हैं। देश का धन देश में रह पाएगा, इसके नियम बनाने होंगे। महंगी शिक्षा निम्न आर्थिक तबके के मेधावी छात्रों के लिए व्यवहार्यक नहीं होगी। यह भी सोचें कि ऊंची फीस देने वाले भारतीय भी भारत में सैटेलाइट यूनिवर्सिटी का विकल्प क्यों चुनना चाहेंगे'.

यूजीसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज के भारतीय कैंपस और यहां उनके परिचालन से जुड़े 'रेग्यूलेशन 2023' लाने जा रही है। इसके पीछे अनेक तर्क दिए जा रहे हैं, जैसे कि इससे ऐसे मेधावी छात्रों को लाभ होगा जो आर्थिक तंगी के कारण प्रसिद्ध विदेशी विश्वविद्यालयों का रुख नहीं कर सकते। कहते हैं कि भारत में अपना स्थानीय कैंपस स्थापित करने वाले कई विदेशी विश्वविद्यालय यहां ट्यूशन फीस में बड़ी छूट भी देंगे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न विश्वविद्यालय, क्वींसलैंड विश्वविद्यालय, अमेरिका का टेक्सस विश्वविद्यालय, सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय और इस्टिटूटो मारांगोनी ने भारत में अपना कैंपस खोलने में रुचि दिखाई है। विदेशी विश्वविद्यालयों के भारतीय कैंपस में गरीब मेधावी छात्रों को उनकी मैरिट के आधार पर स्कॉलरशिप देने का प्रावधान किया जा रहा है। यूजीसी के मुताबिक यह रेगुलेशन अगले कुछ दिनों में जारी किए जा सकते हैं। यूजीसी के मुताबिक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस व इंग्लैंड समेत विभिन्न राष्ट्रों के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने भारत में कैंपस स्थापित करने को लेकर अपनी रुचि दिखाई है। इसके लिए इन विश्वविद्यालयों ने कई सुझाव भी दिए हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों ने अपने सुझावों में क्लस्टर कॉलेज बनाने का सुझाव भी दिया है। यूजीसी ने बताया है कि भारत में कैंपस स्थापित करने की योजना बना रहे विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए मसौदा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देते समय विदेशी विश्वविद्यालयों से प्राप्त सुझावों पर भी विचार किया गया है।

यूजीसी ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया है कि विश्व प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सहित विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपना कैंपस स्थापित करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि विदेशी विश्वविद्यालय के भारत आने पर अनेक फायदे हो सकते हैं। इससे उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और स्वस्थ प्रतिस्पद्र्धा बढ़ेगी। रिसर्च और इनोवेशन पर भी पहले के मुकाबले अधिक काम होगा। छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों व अन्य कर्मियों के लिए रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ उन लाखों भारतीय छात्रों को मिलेगा जो विदेशी विश्वविद्यालयों में आवेदन करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत से हर साल करीब 7-8 लाख छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं। ऐसे में यदि विश्व के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय भारत में ही कैंपस स्थापित करते हैं तो भारतीय छात्रों को स्वदेश में रहकर ही इन विश्वविद्यालयों में पढने का अवसर मिल सकेगा। लेकिन क्या वे देश में पढ़ाई के बाद रहेंगे, यह एक बड़ा सवाल है। यूजीसी का मानना है कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के आने से न केवल डिग्री प्रोग्राम बल्कि रिसर्च को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। दरअसल अभी भी भारत के कई रिसर्चर व प्रोफेसर विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त शोध कर रहे हैं। अभी ऐसे रिसर्चर की संख्या सीमित है, लेकिन भारत में विदेशी कैंपस खुलने पर रिसर्च की संख्या में वृद्धि का अनुमान है। कहते हैं कि भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालय केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त नहीं करेंगे। यही कारण है कि विदेशी विश्वविद्यालय की दाखिला प्रक्रिया व फीस निर्धारण में यूजीसी का सीधा दखल नहीं होगा। लेकिन इन विश्वविद्यालयों को पूरी प्रक्रिया और फीस के मामलों में पारदर्शिता रखनी होगी। उच्च शिक्षा पर हाल ही में जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई 2021) के अनुसार, भारत में 43000 से अधिक कॉलेजों और 1100 से अधिक विश्वविद्यालयों में लगभग 4.14 करोड़ छात्र विभिन्न डिग्री कार्यक्रमों में पढ़ रहे हैं। इस संख्या को संदर्भ में रखने के लिए, भारत एक ऐसा देश है जहां 18 से 23 वर्ष की आयु के लगभग 15.2 करोड़ युवा नागरिक हैं। अब, संख्याओं के इस मिश्रण में, विदेश में पढ़ाई के लिए भारत छोडने वाले छात्रों की गिनती भी जोड़ लें। हाल ही में संसद में प्रस्तुत शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अकेले 2022 में लगभग 7.5 लाख छात्रों ने विदेश में पढने के लिए भारत छोड़ दिया। पिछले साल की तुलना में इस संख्या में 68 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

फिर इस संख्या को संदर्भ में रखने के लिए, किसी को यह ध्यान रखना चाहिए कि कुल छात्रों में से 2 प्रतिशत से भी कम छात्र विदेश में अध्ययन करने के लिए हर साल भारत छोड़ते हैं। हालांकि, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में लाने का विचार केवल इस 2 प्रतिशत को कम करने के बारे में नहीं है। विदेश जाने वाले इनमें से अधिकांश छात्र अपनी शिक्षा का वित्तपोषण स्वयं करते हैं। यह उनके परिवारों द्वारा वहन की जाने वाली एक बड़ी लागत है। 2008 की एसोचैम की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि विदेश में पढने वाले छात्रों की लागत 50000 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके विपरीत भारत में पढने वाले छात्रों द्वारा उच्च शिक्षा पर कुल खर्च भी लगभग 50000 करोड़ रुपये है। विदेश में पढने वाले एक छात्र की प्रति व्यक्ति लागत भारत में पढने वाले एक छात्र की प्रति व्यक्ति लागत से लगभग 100 गुना अधिक है।

स्पष्ट है कि यह लागत कम नहीं होने वाली है, चाहे कोई छात्र किसी विदेशी विश्वविद्यालय में जाए या कोई विदेशी विश्वविद्यालय छात्र के पास आए, ऐसा नहीं लगता कि इस लागत संरचना में कोई खास बदलाव आएगा। फिर विदेशी विश्वविद्यालयों को यहां आने के लिए प्रोत्साहित करना उच्च शिक्षा में निजी पूंजीवाद की पकड़ को मजबूत करना भी हो सकता है, परंतु इसके बावजूद विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए लाने का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में विविधता लाना भी है, जिसकी जरूरत से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावित कदम से इन विश्वविद्यालयों को अपने घरेलू देशों में धन वापस भेजने में मदद मिलेगी। उन्हें अपने पाठ्यक्रमों की फीस तय करने की स्वायत्तता है, जिसका सीधा मतलब यह है कि पाठ्यक्रम महंगे हैं। देश का धन देश में रह पाएगा, इसके नियम बनाने होंगे। महंगी शिक्षा निम्न आर्थिक तबके के मेधावी छात्रों के लिए व्यवहार्यक नहीं होगी। यह भी सोचें कि ऊंची फीस देने वाले भारतीय भी भारत में सैटेलाइट यूनिवर्सिटी का विकल्प क्यों चुनना चाहेंगे? कुल मिला कर भारत को विदेशी विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश करने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए और अपने वर्तमान शिक्षा परिदृश्य में सुधार करना चाहिए। नर्सरी से हाई स्कूल और फिर विश्वविद्यालय स्तर तक हमारी शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल सुधार की आवश्यकता है।

संपादक की कलम से

विकास का अनूठा व्याकरण

'चलो कहीं भरपूर विकास दिखाया जाए, सियासी मिट्टी पर सीमेंट उगाया जाए।' कुछ इसी तरह के उदाहरणों का मिट्टी परीक्षण होता रहा है और वर्तमान सरकार ने भी निरीक्षण-परीक्षण की जिरह पैदा करते हुए, हिमाचल में प्रगति का मुआयना शुरू किया है। संस्थानों की डिनोटिफिकेशन के बाद यह तो साबित हो रहा है कि चुनावी जुबान ने सत्तापक्ष की दिलदारी के नक्शे पर ऐसा नुकसान कर दिया जो प्रदेश के बूते से बाहर है। इसी परिप्रेक्ष्य में तीन अटल आदर्श विद्यालयों की रिपोर्ट भी निराशाजनक स्थिति पैदा कर रही है। जयराम सरकार ने शिक्षा के आदर्शों को सिर पर चढ़ा कर अटल आदर्श विद्यालय का जो ढोल पीटा था, उसकी असलियत अब सामने आ रही है। पहले चरण में 13 अटल विद्यालयों में से मात्र तीन ही जमीन पर उतर पाए और अब पता यह चल रहा है कि इनके ऊपर सौ करोड़ खर्च करके भी छात्र नहीं मिल रहे। यह अनोखे विकास का व्याकरण जिसे राजनीति सिद्ध करना चाहती है। विश£ेषण यह भी बताता है कि जब ऐसी परियोजनाएं बनती हैं, तो उनकी भूमिका से कहीं अधिक पैरवी से क्षेत्रवाद को संतुष्ट किया जाता है। इन विद्यालयों ने भी मंडी के नाचन और धर्मपुर में अपना अड्डा जमाया, जबकि सबसे बड़े कांगड़ा तथा उसके उपरांत शिमला जिला को इसकी फेहरिस्त में कोई दौर नहीं मिला। ऐसी इमारतों के शर्मिंदा होने पर भी हमें कोई नसीहत नहीं मिलती। कुछ साल पहले धर्मशाला-शिमला हाई-वे पर बड़ी महत्त्वाकांक्षा से पर्यटन कक्ष खोला गया, लेकिन इसका आगाज ही इसका अंत बना। इसी तरह नूरपुर में दो बार पर्यटन इकाइयां खोली गईं, लेकिन जनता को सिर्फ एक नालायकी मिली। हमने प्रदेश में तैंतीस स्नातकोत्तर कालेज बना दिए, लेकिन पाठ्यक्रम तो हर विश्वविद्यालय परिसर में हार रहा। सरकार के बेहतरीन विद्यालय अब केवल एक बड़ी इमारत हैं, जो हर मेरिट और परीक्षा परिणाम में निजी स्कूलों से हार रहे हैं। ऐसे में वर्तमान सरकार ने भी अटल आदर्श विद्यालय के सामने राजीव डे बोर्डिंग स्कूल का पंजा लड़ा दिया है। एक विफल प्रयास की दो समानांतर धाराएं बता रही हैं कि कहीं गड़बड़ी व्यवस्थागत है। सार्वजनिक क्षेत्र की हर इमारत को न तो प्रतिस्पर्धा के मायने मालूम हैं और न ही हारने का खौफ है, नतीजतन हिमाचल ने क्षमता से अधिक स्कूल, कालेज, दफ्तर तथा मेडिकल संस्थान खोलकर गुणवत्ता के हिसाब से कुछ भी हासिल नहीं किया। हर बार बीमार होने पर विभिन्न सरकारों के मुख्यमंत्री एम्स दिल्ली रवाना होते रहे, लेकिन हिमाचल के छह सरकारी एक निजी तथा बिलासपुर एम्स-ऊना पीजीआई सेटेलाइट सेंटर खोलकर भी हमारी स्वास्थय सेवाएं बाहरी प्रदेशों पर आश्रित हैं। अभिभावक तलाश में हैं कि उनके बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा कहां मिलेगी, मरीज पीजीआई चंडीगढ़ या लुधियाना के अस्पताल तक पहुंचना चाहते हैं। अगर निकम्मे साबित हो रहे स्कूल-कालेजों की इमारतों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाया जाए, तो भी शिक्षा का भला हो सकता है, वरना जो अटल आदर्श विद्यालय बन न कर सका, वह राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बन कर क्या कर पाएगा। हिमाचल में अब भी कई स्कूल-कालेजों, दफ्तरों व चिकित्सा संस्थानों को बंद करने की जरूरत है ताकि सार्वजनिक क्षेत्र की नाक बचाई जा सके, वरना धीरे-धीरे लोगों की हर सेवा के लिए निजी क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ती जाएगी। प्रदेश सरकार प्रमुख शहरों के सरकारी स्कूलों को या तो सीबीएसई या आईसीएसई पाठ्यक्रम के तहत चलाए तो भी अंतर आएगा। दूसरी ओर प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का करियर के हिसाब से कुछ स्कूलों को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर दसवीं परीक्षा के आधार पर शिक्षा बोर्ड टेलेंट सर्च करके पांच हजार बच्चों को मेरिट के आधार पर बोर्डिंग स्कूल उपलब्ध कराए, तो प्रदेश में एक दर्जन करियर विद्यालय बन सकते हैं। जमा एक व जमा दो कक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड बड़े शहरी स्कूलों का हुलिया व मांग बदल सकता है। इतना ही नहीं ऐसी ही मेरिट के आधार पर ये स्कूल छात्रों को राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं तथा राष्ट्रीय स्तर के रोजगार के अलावा विभिन्न खेलों के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। इसी तरह हर विश्वविद्यालय कुछ कालेजों को गोद लेकर इन्हें विषय विशेष का राज्यीय या राष्ट्रीय संस्थान बनाने में मेहनत करे, तो शिक्षा का स्तर किसी और आसमान पर पहुंच जाएगा, वरना सरकारें तो इमारतों की मंडी में कभी शिक्षा तो कभी चिकित्सा को बेचती नजर आएंगी।

राय

यह सिर्फ मैच नहीं

क्योंकि यह हिमाचल के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में हुआ, इसलिए प्रकृति के विहंगम दृश्यों का समावेश वल्ड मैचों की श्रृंखला का श्रृंगार बढ़ा गया। खास तौर पर जब बादलों की एक टोली स्टेडियम में आई और मैच की निगाहों में वो फलसफा बन गए जो जानते नहीं थे कि यहां तो कृत्रिम प्रकाश में भी खलल पड़ जाएगा। एक अच्छी क्रिकेट रविवार की दोपहरी में उगी और शाम से रात आते-आते पर्यटन की नजरों में समा गई। बेशक अच्छी क्रिकेट ने मन, भारतीय टीम ने दिल जीता, लेकिन दर्शक दीर्घा का वीआईपी अंदाज सियासी वीरता के नगमों में तल्लीन रहा। कितना सौहार्द है इस पैमाने में, न होंठ तेरे बुझे, न मेरे जले। उस हंसी की बिसात का कोई टिकट नहीं और न ही कहीं से पकड़े जाने का गिला। पकड़े तो स्टेडियम से बाहर दर्शक गए, क्योंकि नकली टिकट बिक रहे थे। ब्लैकमेल भी इसी स्टेडियम के इसी मैच की निशानी दे गया। सब कुछ घर जैसा था, सिर्फ प्रदेश में कुछ अलग था क्योंकि वहां स्टेडियम के बादलों से भिन्न जिन बादलों ने घर उजाड़े थे, उसकी शिकन कहां क्रिकेट के मनोरंजन में खलल डाल सकती होगी। यहां तो ताली भी वीआईपी अंदाज में बजनी थी, तो खूब बजी। एक हाथ भाजपा तो दूसरा कांग्रेस का बजा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वहां क्रिकेट के मसीहा थे, वैसे वह आजकल हमीरपुर से कांगड़ा तक की सडक़ों पर छाए हैं और क्रिकेट के प्रशंसकों का स्वागत करते नहीं थक रहे, लेकिन स्टेडियम में जो आए, उन्हीं के बुलावे पर आए, वरना इस शहर को तो बस मिला यातायात प्लान, मीलों के घुमाव और जाम में ठहराव।

बेशक कुछ होटल भर गए, लेकिन स्टेडियम में वही खुशनसीब थे जिन्हें पास के साथ मुफ्त भोजन का ईनाम मिला, वरना स्टैंड में बिकते पानी की कीमत सुनकर तो पसीना दर्शकों को भी खूब आया होगा। वहां कितने क्रिकेट प्रेमी और कितने सियासी सैलानी रहे होंगे, यह तुलनात्मक अध्ययन की बिसात तय करेगी। यह दीगर है कि जहां कैमरों की निगरानी में खुशामदीद कहा जा रहा था, वहीं खेलों का हिमाचली नायक नदारद था। बेहतर होता उस हुजूम में एक अदद निमंत्रण एशियन गेम्स से लौटे हिमाचली खिलाडियों का चेहरा भी दिखा देता। वाकई कबड्डी के अंतरराष्ट्रीय मैदानों से उस दिन बहुत बड़ा था क्रिकेट का स्टेडियम। कितने छोटे हैं बिलासपुर की स्नेहलता के प्रयास, जिसने अपने खेतों में प्रशिक्षण देते हुए हैंडबाल की ऐसी नर्सरी उगा दी जो देश के लिए अंतरराष्ट्रीय तमगे ले आती है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की रौनक के ठीक नीचे भारतीय खेल प्राधिकरण का स्टेडियम और समीपवर्ती कालेज की घास भी रही होगी, जिसकी जमीन पर उपर्युक्त स्टेडियम बना है। वे पंख भी उड़ान भरना भूल गए जो इंद्रूनाग, बीड़-बिलिंग व नरवाना साइट से पैराग्लाइडिंग के इतिहास को आकाश में ले जाना चाहते थे। बहुत पहले जब क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण राजनीतिक आंखों की किरकिरी बना था, तब अचानक कांग्रेस सरकार ने ताले जड़े थे। क्या वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के स्टेडियम प्रवेश से पूरी तरह टूट गए। क्या खेलों में इसी तरह का सौहार्द धर्मशाला में हाई अल्टीच्यूट स्पोर्ट्स सेंटर को भी नसीब होगा। वहां खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ क्रिकेट मुस्कराई, लेकिन ठीक इसी स्टेडियम के बगल में कोई धर्मशाला खेल एक्सीलेंस सेंटर के तहत राष्ट्रीय खेल छात्रावास के लिए आए 26 करोड़ के बजट को निगल चुका था। यह छात्रावास निचले सकोह में प्रस्तावित था, लेकिन दुनिया तो अब सिर्फ क्रिकेट देखती है और समझती है कि हमने कितना जश्न पैदा किया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर केवल एक एथलीट के कारण भी देश का राष्ट्रगान बज उठता है। कभी तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने धर्मशाला को खेल नगरी या राजधानी कहा था।

शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता आज की जरूरत

यह कहने में कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि प्राइवेट स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। इसके अतिरिक्त शिक्षा नीति तैयार करते समय हर बार राजनीतिक दबाव डाला जाता है'

शिक्षा भविष्य का निर्माण करने का प्रभावी और उपयोगी माध्यम है। शिक्षा से ही समाज का निर्माण होता है और शिक्षा से ही सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक स्तर को उच्च बनाया जा सकता है। राज्य में बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा आसानी से मिले, इसके लिए शासन ने छोटे से छोटे गांव में प्राथमिक पाठशालाएं शुरू की हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और महाविद्यालय स्तर की शिक्षा का विस्तार हुआ है। स्वतंत्रता के समय हिमाचल में लोग अत्यंत गरीब और पिछड़े थे और उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं थीं। यह वह समय था, जब हिमाचल में नाममात्र ही विद्यालय हुआ करते थे। वर्ष 1947 में जहां राज्य की साक्षरता दर मात्र आठ प्रतिशत थी, जो आजादी के बाद साल दर साल सुधर कर 1971 में 31.96 और 2001 में 76.5 प्रतिशत थी। वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर बढक़र 82.80 प्रतिशत से अधिक हो गई है। हिमाचल की साक्षरता दर पूरे देश की साक्षरता दर से अधिक है। इतना ही नहीं हिमाचल में महिला साक्षरता दर भी 75.93 प्रतिशत है जो कि कई राज्यों की तुलना में अधिक है। इसका श्रेय प्रदेश में रही सरकारों और हिमाचल प्रदेश के मेहनतकश लोगों को जाता है। आज प्रदेश में 140 महाविद्यालय हैं।

प्रदेश में हायर एजुकेशन के लिए पांच स्टेट यूनिवर्सिटीज और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इंस्टिट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में आईआईटी मंडी, एनआईटी हमीरपुर, आईआईएम सिरमौर, सीआरआई कसौली में स्थित है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में असंख्य प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। राज्य में 18028 स्कूल हैं जिनमें से 15313 सरकारी हैं। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इनफार्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 12 प्राथमिक सरकारी स्कूल बिना शिक्षक के चल रहे हैं, जबकि 2969 में एक शिक्षक, 5533 में दो शिक्षक और 1779 में तीन शिक्षक हैं। इसी तरह 51 मिडिल स्कूल एक शिक्षक द्वारा, 416 दो शिक्षकों द्वारा, 773 तीन शिक्षकों द्वारा और 701 चार से छह शिक्षकों द्वारा चलाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि न्यूनतम 10 कक्षाओं वाला एक माध्यमिक विद्यालय दो शिक्षकों द्वारा, 10 विद्यालय तीन शिक्षकों द्वारा, 212 विद्यालय चार से छह शिक्षकों द्वारा और 710 विद्यालय सात से 10 शिक्षकों द्वारा चलाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन के सरकारी दावों पर सवाल खड़े करते हैं। सरकार को जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम है, उन सभी स्कूलों को बंद करके, बच्चों को नजदीक के स्कूलों में शिफ्ट करना चाहिए। सरकार को नजदीक के स्कूल में शिफ्ट किए बच्चों को सरकारी खर्च पर बस की या हॉस्टल की सुविधा प्रदान करनी चाहिए ताकि बच्चों के अभिभावकों पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े। पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों की उपलब्धता में काफी वृद्धि हुई है जिसके कारण हिमाचल के लोगों के लिए शिक्षा सुगम हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या हिमाचल प्रदेश शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता को बना कर रख पाया है? अगर हम आज भी धरातल पर देखें तो पाएंगे कि आजादी के वर्षों बाद भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और स्कूली शिक्षा की स्थिति दयनीय है।

राज्य के अधिकांश गांवों में अभी भी स्कूलों और कॉलेजों की कमी है, तो कई स्थानों पर बिना किसी गुना-भाग के सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं। स्कूल और कॉलेज सिर्फ ईंट और पत्थर की दीवार नहीं होती है। अगर स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग शरीर है तो उसमें अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षक उस शरीर की आत्मा होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्कूल बिना टीचर्स के या सिर्फ मात्र एक या दो शिक्षकों के सहारे चल रहे हैं। कहीं स्कूल भवन अच्छे हैं, तो वहां शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो कहीं इमारत भी ठीक है, शिक्षक भी हैं, लेकिन विद्यार्थी नहीं हैं। इसके अलावा कुछ एक शिक्षकों का रवैया भी शिक्षा के प्रति सकारात्मक नहीं रहता। सरकारी स्कूलों में कक्षाओं का न लगना, अध्यापकों का स्कूलों में समय पर न पहुंचना, ये सब कारण स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में रोड़ा बनते हैं। आज हम देखते हैं कि एक गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चे को अपने गांव या शहर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करता है। जो शिक्षक सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, वह भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूल में शिक्षा देना बेहतर समझता है। लोगों के बीच एक जनरल परसेप्शन है कि सरकारी स्कूलों में पठन-पाठन का कार्य सही ढंग से नहीं होता। अभी कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी के सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढने वाले बच्चे उस समय अपने देश का नाम भी नहीं बता पाए जब भरमौर के विधायक डॉ. जनकराज वहां निरीक्षण के लिए पहुंचे।

यह कहीं न कहीं सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता के सरकारी दावों के ऊपर प्रश्नचिन्ह लगाता है। पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा का स्तर धीरे-धीरे नीचे गिरता जा रहा है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण राजनेताओं ने बिजनेसमैन को स्कूल-कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी। स्कूल खोलने की अनुमति देते समय जिन नियमों का पालन किया जाना था उनका पालन नहीं किया गया एवं स्कूल और कॉलेज गलत हाथों में चले गए। बहुत से लोगों के लिए शिक्षा मात्र एक व्यवसाय का जरिया बन गया है। अभिभावकों को कभी फीस के नाम पर तो कभी ड्रेस के नाम पर खूब लूटा जा रहा है। बहुत से प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों को पूरा वेतन नहीं मिलता और नौकरी के नाम पर उनका शोषण किया जाता है। बहुत से प्राइवेट स्कूल टीचर्स को हायर करते हुए बेसिक क्वालिफिकेशन को भी दरकिनार कर देते हैं। यह कहने में कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि प्राइवेट स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। इसके अतिरिक्त शिक्षा नीति तैयार करते समय हर बार राजनीतिक दबाव डाला जाता है। अयोग्य लोगों को पदों पर नियुक्त किया जाता है। आज प्रदेश में जरूरत इस बात की है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए सभी उपाय किए जाएं।

छिलकों की छाबड़ी : उत्सव, बाजार और लाचार

काश! मेरा देश उत्सवों, त्योहारों का देश न होता। होता तो मेरी प्रिया उत्सवप्रिय न होती। अब तो मुहल्ले में अपनी पूरी तरह गिर चुकी साख बनाए रखने के लिए हर त्योहार मजबूरी में खुशी खुशी लोन की पालकी में पलटियां खाते रोते रोते मनाना पड़ रहा है। अब त्योहार मनाने की उतनी खुशी नहीं होती जितनी पिछले से अधिक लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड के मिलने की होती है। अब जीने के लिए सांस उतनी जरूरी नहीं लगती जितना जरूरी लोन लगता है। अब तो भगवान से यही प्रार्थना कि वह मुझसे जैसे कैसे महीने बाद क्रेडिट कार्ड पर लिया क्रेडिट जैसे कैसे इससे उससे उधार ले लौटवाता रहे। हे दिल खोलकर उत्सवों के दिनों में हम बाजार के मारों को क्रेडिट कार्ड ऑफर करने वाले बैंकों! भगवान आपके क्रेडिट कार्ड देने के इस लचीलेपन को सदा सदा को बनाए रखे। अबके फिर पता नहीं चल रहा कि पहले उत्सव मनाऊं या बाजार जाऊं? हर उत्सव के दिनों बाजार मुझे अपनी ओर खींचता है तो उत्सव अपनी ओर। और मैं बेचारा तब न बाजार का ही हो पाता हूं और न उत्सव का ही। मतलब, मिडल क्लास कुत्ता उत्सव का न बाजार का। आदमी इनसानियत के बिना अधूरा हो या न, पर बिन बाजार के वह अधूरा ही अधूरा है। हमारे छोटे से छोटे उत्सव को भी जो कोई यादगार बनाता है तो वह बाजार ही है। बिन बाजार के उत्सव उत्सव नहीं लगता। उत्सव की रौनक बाजार से है। बाजार ही हर उत्सव के आने की सूचना देता है। आज की तारीख में जो बाजार न होता तो हमें पता ही न चलता कि कौनसा बार त्योहार कब है। उत्सवों के दिनों में अखबार विज्ञापनों के भार से इतने दब हो जाते हैं, वसंत आने पर फूलों से सूखे पेड़ तक ज्यों। तब अखबार वाले को हमारी बालकनी में अखबार फेंकने को पूरा जोर लगाना पड़ता है। कल कह रहा था कि वह दिवाली तक अखबार गेट के बाहर ही रखा करेगा। बालकनी में अखबार फेंकते हुए उसकी बाजू में दर्द हो रही है। आजकल सुबह जैसे ही अखबार आता है तो हम दोनों में अखबार को लेकर जोर आजमाइश होती है। श्रीमती अखबार में नए नए प्रॉडक्ट के विज्ञापन जी भर निहारना चाहती है तो मैं रोज की तरह आज का ताजा राशिफल। यह दूसरी बात है कि राशि के फल के हिसाब से मुझे फल आज तक नहीं मिला। पर चलो, इस बहाने दो पल को ही सही, मन प्रसन्न हो जाता है। सारे दिन की भाग दौड़ की जिंदगी से शुभ राशिफल के दो सुखद काल्पनिक पल बहुत अच्छे होते हैं। और तब मैं अखबार पहले पाने की लड़ाई में हर बार की तरह अबके फिर न चाहते हुए भी हार जाता हूं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद से ही गृहस्थी में हर गेम हारना मेरी नियति है या मेरा स्वभाव, मुझे कुछ मालूम नहीं। पर इसहार का एक बहुत बड़ा फायदा है, और वह यह कि घर हर लेबल के कलह क्लेशों से बचा रहता है। एक शांति प्रिय पति को इससे अधिक गृहस्थी से और चाहिए भी क्या? जो अपनी गृहलक्ष्मी से परेशान हों उनके लिए मेरी मुफ्त की सलाह कि वे जानबूझ कर अपनी बेगम से बात बात पर हारते रहें। घर और मन दोनों बहुत शांत रहेंगे। गृहस्थी की जंग में जो मजा पति के हारने में है वैसा मजा दीपावली के रोज जुए में जीतने में भी नहीं। कलके अखबार में फिर विज्ञापन छपा था- अबके दीपावली है बहुत विशेष, कोई खरीददारी न छोड़ें शेष। भैया जी! इस विशेष के चक्कर में पड़ बीवी ने बाजार जाकर आज तक कुछ छोड़ा है क्या जो अबके छोड़ेगी? अब और खरीददारी करवाके शरीफ हसबेंड का और बैंड बजवाओगे क्या? चार चार क्रेडिट कार्ड में जितनी लिमिट थी, उस सबकी सीमा तो बाजार के बहकावे में आकर दीपावली से पहले ही बीवी वैतरणी की तरह लंघवा चुकी है। बीवी शॉप शॉप उत्सव की दुहाई देते मेरा हौसला बढ़ाती मुझे बाजारू ज्ञान देती मेरी टूटी कमर पर जैसे कैसे थमी पीठ को थपथपाती कह रही है कि इस दीपावली की खरीददारी में क्रेडिट कार्ड देने वाले बैंकों का डिफाल्टर हो जाऊं तो दीपावली का मजा ही कुछ और हो।

आईआरसीटीसी ने जारी किये Q2 के नतीजे

सितंबर तिमाही में 30 फीसदी बढ़ा मुनाफा

आईआरसीटीसी ने बुधवार को सितंबर तिमाही 2023-24 के नतीजे जारी किये हैं। इस नतीजे में आईआरसीटीसी ने बताया कि उनका नेट प्रॉफिट यानी कि कुल मुनाफा सितंबर तिमाही में 30 फीसदी बढ़कर 294.67 करोड़ रुपये हो गया था। आज आईआरसीटीसी के शेयर 676 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे हैं।

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिये हैं। इस नतीजे में कंपनी ने बताया कि उनके नेट प्रॉफिट में बढ़त हासिल हुई है। सितंबर तिमाही 2023-24 के लिए नेट प्रॉफिट में 30.36 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 294.67 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की।

बीएसई फाइलिंग में कहा गया है कि कंपनी ने एक साल पहले की अवधि में 226.03 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।

आईआरसीटीसी के रेवेन्यु में बढ़त

भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम ने कहा कि कुल राजस्व Q2FY23 में 805.80 करोड़ रुपये की तुलना में 23.51 फीसदी बढ़कर 995.31 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने कहा कि उसके बोर्ड ने प्रति इक्विटी शेयर 2.50 रुपये का अंतरिम लाभांश घोषित किया है।

आईआरसीटीसी की कल्पना भारतीय रेलवे की एक विस्तारित शाखा के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य स्टेशनों, ट्रेनों और अन्य स्थानों पर खानपान और आतिथ्य सेवाओं को उन्नत करना, पेशेवर बनाना और प्रबंधित करना था। इसके अतिरिक्त, यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दोनों को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। यह कंपनी रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है।

आज कंपनी के शेयर 3.60 की गिरावट के साथ 677.50 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है।

डॉलर के मुकाबले मजबूत हुई भारतीय करेंसी, इतने पैसे की आई बढ़त

भारतीय शेयर बाजार में जारी सकारात्मक रुख ने भारतीय करेंसी पर भी असर डाला है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे की बढ़त के साथ खुला था। वहीं मंगलवार के कारोबारी सत्र में रुपया गिरावट के साथ बंद हुआ है। ग्लोल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है।

नई दिल्ली। शेयर बाजार में नरम रुख और विदेशी बाजार में अमेरिकी मुद्रा की मजबूती के बीच बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि विदेशी फंड की निरंतर निकासी ने भी निवेशकों की भावनाओं को प्रभावित किया है। आज इंटरबैंक विदेशी मुद्रा में, घरेलू इकाई डॉलर के मुकाबले 83.25 पर खुली और फिर 83.23 के शुरुआती उच्च स्तर को छू गई, जो पिछले बंद के मुकाबले 4 पैसे की बढ़त दर्शाता है। बीते दिन मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83.27 पर बंद हुआ। इस बीच, वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.02 प्रतिशत बढ़कर 81.63 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। डॉलर इंडेक्स में डॉलर 0.03 प्रतिशत बढ़कर 105.05 पर कारोबार कर रहा था।

फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी के ट्रेजरी प्रमुख और कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार भंसाली ने कहा फेड नीति अनिश्चितता और चीन और यूरोप जैसे प्रमुख आयातकों की असंगत मांग के बीच ब्रेंट तेल की कीमतें गिरकर 81.62 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गईं। सोमवार से एशियाई मुद्राओं में बढ़त के बावजूद बाहरी प्रेषण भारतीय रुपये पर हावी हो रहा है।

S&P ने बरकरार रखा भारत के विकास दर का अनुमान, कहा- भारतीय अर्थव्यवस्था का मजबूत विकास वाला ट्रैक रिकॉर्ड

वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल ने अपने 2024 आउटलुक में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के 6 प्रतिशत के विकास अनुमान को दोहराया और कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मजबूत विकास का ट्रैक रिकॉर्ड है। एसएंडपी के अनुसार भारत की वृद्धि पूंजी की धीरे-धीरे बढ़ती लागत अनुकूल जनसांख्यिकी और बढ़ती उत्पादकता से प्रेरित है। पढ़िए क्या है पूरी खबर।

नई दिल्ली। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने अपने आउटलुक 2024 में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर का अनुमान 6 प्रतिशत पर बरकरार रखते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था का ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत ग्रोथ वाला रहा है। एसएंडपी ने बताया कि धीरे-धीरे पूंजी का बढ़ना, अनुकूल जनसांख्यिकी और उत्पादकता में सुधार ने भारत के विकास को बढ़ाया है।

एसएंडपी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था का मजबूत विकास का ट्रैक रिकॉर्ड है। हमें उम्मीद है कि यह गति जारी रहेगी और वित्त वर्ष 2024 के लिए 6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, फिर वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 के लिए 6.9 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

विकास में क्या रह सकती है चुनौतियां?

रिपोर्ट में एसएंडपी ने कहा कि विकास के अगले चरण में श्रम बल की भागीदारी, जलवायु लचीलापन और कारोबारी माहौल में और सुधार शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर उद्योगों में मजबूत विकास प्रदर्शन पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का प्रभाव समय के साथ बढ़ा है, जबकि कृषि और अन्य प्राथमिक उद्योगों ने आर्थिक हिस्सेदारी कम हुई है।

एसएंडपी को जानिए

एसएंडपी ग्लोबल वैश्विक स्तर पर पूंजी और कमोडिटी बाजारों को क्रेडिट रेटिंग, बेंचमार्क, डेटा और डिजिटल और पारंपरिक वित्तीय अनुसंधान और विश्लेषणात्मक उपकरण प्रदान करता है।

इनसाइड

चाइनीज प्रोफेशनल्स के वीजा मंजूरी को सरकार ने किया सुव्यवस्थित, बनाया एसओपी

भारत सरकार ने चीनी पेशेवरों को वीजा की समस्या को सुलझाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। एक अधिकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने वीजा मंजूरी को सुव्यवस्थित करने के लिए एसओपी बनाया है। यह एसओपी उन चीनी विशेषज्ञों के लिए है जिनकी विशेषज्ञता प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम के तहत प्रदाताओं को आवश्यक है।

नई दिल्ली। भारत सरकार ने चाइनीज प्रोफेशनल्स के भारत में वीजा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। एक अधिकारी के मुताबिक सरकार ने चाइनीज प्रोफेशनल्स के वीजा मंजूरी को सुव्यवस्थित करने के लिए एसओपी तैयार किया है। ये एसओपी उन चाइनीज प्रोफेशनल्स के लिए है जिनकी एक्सपर्टीज की जरूरत वेंडरों को पीएलआई स्कीम के तहत है।

चीनी प्रोफेशनल्स ने उठाया था वीजा का मुद्दा

अगस्त में पीएलआई योजना पर कुछ चीनी प्रोफेशनल्स ने वीजा मुद्दे को उठाया था। हालांकि उस वक्त सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया था कि इस समस्या को सुलझाने का प्रयास सरकार कर रही है। अधिकारी ने कहा हमने वीजा मुद्दे को इस अर्थ में हल कर लिया है कि हमने पीएलआई इकाइयों के लिए एक एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) बनाई है। उनके वीजा के लिए, हमारे पास एक प्रणाली है जिसके तहत उनके वीजा अनुमोदन को सुव्यवस्थित किया जाएगा।

क्या है पीएलआई स्कीम?

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य कंपनियों को घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बढ़ती बिक्री पर प्रोत्साहन देना है। पीएलआई योजना की घोषणा 2021 में टेलीकॉम, सफेद सामान, कपड़ा, चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, विशेष इस्पात, खाद्य उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, उन्नत रसायन विज्ञान सेल बैटरी, ड्रोन और फार्मा जैसे 14 क्षेत्रों के लिए की गई थी।

धनतेरस से पहले सोने-चांदी में आई तेजी, जानिए आपके शहर में क्या लेटेस्ट रेट

देश में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है। दो दिन के बाद देश में धूमधाम से धनतेरस मनाया जाएगा। इस दिन लोग सोने और चांदी की सिक्के खरीदते हैं। ऐसे में धनतेरस से पहले सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। जानिए आपके शहर में क्या है गोल्ड की क्या कीमत है।

नई दिल्ली। धनतेरस के मौके पर अगर आप सोना खरीदने का सोच रहे थे तो आपको बता दें कि आज सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त हुई है। ऐसे में आपके शहर में सोने और चांदी का क्या भाव है यह आपको पता होना चाहिए।

सोने की कीमतों में तेजी

मजबूत हाजिर मांग के कारण सटोरियों ने ताजा सौदों की लिवाली की जिससे वायदा कारोबार में बुधवार को सोने की कीमत 53 रुपये बढ़कर 60,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 53 रुपये या 0.09 प्रतिशत बढ़कर 60,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 12,767 लॉट का कारोबार हुआ।

वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में सोना वायदा 0.03 प्रतिशत बढ़कर 1,974.10 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस हो गया।

1 किलो चांदी हुई महंगी

बुधवार को वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 205 रुपये बढ़कर 70,839 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, क्योंकि मजबूत हाजिर मांग के कारण प्रतिभागियों ने अपने सौदे बढ़ा दिए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी अनुबंध 205 रुपये या 0.29 प्रतिशत बढ़कर 22,845 लॉट में 70,839 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया।

वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में चांदी 0.27 प्रतिशत बढ़कर 22.65 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।

आपके शहर में क्या है सोने की कीमत

गुड रिटर्न वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत इस प्रकार है:

दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,350 रुपये है।

नोएडा में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,350 रुपये है।

मुंबई में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,200 रुपये है।

चैन्नई में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,750 रुपये है।

कोलकाता में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,200 रुपये है।

बेंगलुरु में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,200 रुपये है।

केरल में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,200 रुपये है।

पटना में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,250 रुपये है।

सूरत में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,250 रुपये है।

चंडीगढ़ में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,350 रुपये है।

लखनऊ में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,350 रुपये है।

दिवाली के दिन इस समय कर पाएंगे ट्रेडिंग, धन कमाने का है 'शुभ मुहूर्त', जानिए क्या है टाइमिंग

अब आप दिवाली के दिन यानी कि 12 नवंबर 2023 को ट्रेडिंग और निवेश करके लाभ कमा सकते हैं। दरअसल शेयर बाजार में दिवाली की छुट्टी रहती है लेकिन अब आप BSE और एनएसई पर स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग में एक घंटे के लिए कारोबार कर सकते हैं। दोनों प्रमुख स्टॉक इंडेक्स में यह विशेष ट्रेडिंग सत्र आयोजित करेंगे।

नई दिल्ली। शेयर बाजार से मुनाफा कमाने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब आप दिवाली वाले दिन यानी 12 नवंबर 2023 को भी ट्रेडिंग और निवेश कर मुनाफा कमा सकते हैं।

दरअसल दिवाली वाले दिन शेयर बाजार में छुट्टी रहती है लेकिन अब एक घंटे के लिए आप बीएसई और एनएसई पर स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग (Special Muhurat Trading) का में कारोबार कर सकते हैं। शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक इस स्पेशल ट्रेडिंग सेशन का आयोजन करेंगे।

Muhurat Trading timing 2023

ट्रेड इवेंट	समय
ब्लॉक डील सत्र	5:45 PM - 6:00 PM
प्री-ओपन सत्र	6:00 PM - 6:08 PM
मुहूर्त ट्रेडिंग	6:15 PM - 7:15 PM
कॉल ऑक्शन सत्र	6:20 PM - 7:05 PM
समापन सत्र	7:25 PM - 7:35 PM

नए विक्रम संवत की शुरुआत का प्रतीक

स्पेशल सेशन एक नए संवत की शुरुआत का भी प्रतीक है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक नया साल दिवाली से शुरू होता है और ऐसा माना जाता है कि 'मुहूर्त' या शुभ घंटे के दौरान व्यापार हितधारकों के लिए समृद्धि और वित्तीय विकास लाता है। **दिवाली पर कुछ भी नया शुरू करना अच्छा**

मार्केट विशेषज्ञों के मुताबिक दिवाली कुछ भी नया शुरू करने का आदर्श समय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि निवेशकों को पूरे वर्ष इस सत्र के दौरान व्यापार करने से लाभ होता है।

LIC की पॉलिसी हो गई है बंद, दोबारा शुरू करने के लिए फॉलो करें यह स्टेप्स

परिवहन विशेष न्यूज

निवेश के लिए एलआईसी पॉलिसी काफी लोकप्रिय है। कई लोग एलआईसी पॉलिसी करवाते हैं पर समय पर प्रीमियम का भुगतान नहीं करने पर उनकी पॉलिसी बंद हो जाती है। ऐसे में पॉलिसी को दोबारा शुरू करने पर कितना चार्ज लगेगा और उसके क्या नियम है इसके बारे में आज हम आपको आर्टिकल में बताएंगे।

नई दिल्ली। भारतीय जीवन बीमा (LIC) जहां कई तरह के पॉलिसी की जा सकती है। कई बार समय पर प्रीमियम न भरने की वजह से एलआईसी पॉलिसी बंद हो जाती है। आपको बता दें कि आज के समय में खुद के साथ खुद की फैमिली को सिक्योर करने के लिए पॉलिसी करवाना बेहद जरूरी होता है।

अगर आपने भी कोई एलआईसी पॉलिसी ली है तो आपको समय से उसे रिन्यू करवाना चाहिए। अगर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो आप उसे दोबारा शुरू कर सकते हैं। जब भी कोई पॉलिसी बंद होती है तो बीमा कंपनी 2 साल का रिवाइज करने का मौका देती है। इसक मतलब है कि इस समय कोई भी ग्राहक आसानी से प्रीमियम का भुगतान करके दोबारा पॉलिसी शुरू कर सकता है।

लैप्स पॉलिसी क्या है

पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए हमें कवरेज का भुगतान करना होता है। अगर हम समय से प्रीमियम का भुगतान नहीं करते हैं तो बीमा पॉलिस बंद हो जाती है यानी कि हमें उसका लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में पॉलिसी को दोबारा शुरू करने के लिए सभी बकाया प्रीमियम और ब्याज का भुगतान करना होता है। वहीं, भारतीय जीवन बीमा निगम के पास पॉलिसी को दोबारा शुरू करने या फिर अस्वीकार करने का अधिकार होता है।

पॉलिसी को दोबारा शुरू कैसे करें

पॉलिसीधारक को अपने सभी ब्याज का भुगतान करना होता है।

बीमा कंपनियों द्वारा जारी नियमों व शर्तों के आधार पर ही पॉलिसी को दोबारा शुरू किया जा सकता है।

पॉलिसी को दोबारा शुरू करने के लिए पॉलिसीधारक को एजेंट या फिर ब्रांच में जाकर एलआईसी पॉलिसी पुनरुद्धार की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

वह ग्राहक सेवा को कॉल करके भी पूछताछ कर सकते हैं।

पॉलिसी को दोबारा शुरू करने के लिए जो भी विशेष रिपोर्ट या मेडिकल रिपोर्ट की आवश्यकता होती है उसका भुगतान पॉलिसीहोल्डर द्वारा किया जाएगा।

96 वर्ष के हुए लालकृष्ण आडवाणी; PM मोदी, राजनाथ सिंह सहित इन भाजपा नेताओं ने घर जाकर दी बधाई

परिवहन विशेष न्यूज

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को भाजपा के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट कर जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि आडवाणी जी के आवास पर जाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को भाजपा के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट कर जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई अन्य नेतागण मौजूद रहे।

96 वर्षीय लालकृष्ण आडवाणी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात का वीडियो समाचार एजेंसी एएनआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अन्य नेता भी दिखाई दे रहे हैं।

PM मोदी ने शेयर की तस्वीरें

प्रधानमंत्री मोदी ने भी 'एक्स' पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि आडवाणी जी के आवास पर जाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

क्या कुछ बोले अमित शाह ?

गृह मंत्री अमित शाह ने 'एक्स' पर पोस्ट किया,

आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आडवाणी जी ने अपने अथक परिश्रम और संगठन कौशल से पार्टी को सींचने और कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम किया। भाजपा की स्थापना से लेकर सत्ता तक आने में आडवाणी जी का अतुलनीय योगदान हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा का अक्षुण्ण स्रोत है। ईश्वर से उनकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।

'अप्रतिम योगदान'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं हम सबके प्रेरणास्रोत लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय राजनीति के वे एक प्रमुख स्तंभ रहे हैं और भाजपा संगठन को भी उन्होंने बहुत मजबूती प्रदान की है। सार्वजनिक जीवन में लंबे समय तक सक्रिय रहे आडवाणी जी का योगदान अप्रतिम है। मैं ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य की और दीर्घजीवी होने की कामना करता हूं।

रोहिंग्या का घुसपैठ कराने वाले गिरोहों पर कसा शिकंजा,10 राज्यों में 55 स्थानों पर NIA के छापे

रोहिंग्या का घुसपैठ कराने वाले गिरोहों पर एनआइए ने शिकंजा कसा है। अवैध घुसपैठ कराने वाले गिरोह के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एनआइए ने 10 राज्यों में कुल 55 स्थानों पर छापा मारा। छापे के दौरान बड़ी संख्या में आधारकार्ड और पैनकार्ड बरामद किये गएजिनके फर्जी होने का संदेह है। एनआइए ने असम पुलिस की जांच अपने हाथ लेते हुए छह अक्टूबर को नई एफआइआर दर्ज की थी।

नई दिल्ली। NIA ने म्यांमार से रोहिंग्या का भारत में घुसपैठ कराकर विभिन्न राज्यों में बसाने वाले चार गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 44 आरोपियों को हिरासत में लिया है। अवैध घुसपैठ कराने वाले गिरोह के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एनआइए ने 10 राज्यों में कुल 55 स्थानों पर छापा मारा।

छापे के दौरान बड़ी संख्या में आधारकार्ड और पैनकार्ड बरामद किये गए, जिनके फर्जी होने का संदेह है। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन, सिम कार्ड और पेन ड्राइव के साथ-साथ 20 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 4450 अमेरिकी डालर भी जब्त किये गए।

असम पुलिस की कार्रवाई

एनआइए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, असम पुलिस द्वारा नौ सितंबर को रोहिंग्या के घुसपैठ कराने वाले गिरोह के खिलाफ दर्ज एफआइआर की जांच के दौरान उनके नेटवर्क के बारे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। एनआइए ने असम पुलिस की जांच अपने हाथ लेते हुए छह अक्टूबर को नई एफआइआर दर्ज की थी।

NIA ने दर्ज की तीन FIR

इस नेटवर्क की जांच के दौरान तीन और नेटवर्क के सक्रिय होने का सबूत सामने आए और उसके आधार पर एनआइए ने तीन नई एफआइआर दर्ज की। इस तरह से रोहगिया का अवैध घुसपैठ कराने वाले कुल पांच गिरोह से जुड़े नेटवर्क की जांच शुरु हुई। एनआइए के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अवैध घुसपैठ कराने वाला नेटवर्क असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों के साथ-साथ तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर तक फैला हुआ था। इसके लिए गिरोह के सदस्य फर्जी आधारकार्ड और पैनकार्ड जैसे दस्तावेज तक तैयार कर लेते थे।

वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार हिरासत में लिए गए 44 आरोपियों को गुरूवार को अदालत में पेश किया जाएगा और हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी।एनआइए की जांच में त्रिपुरा रोहिंग्या घुसपैठ के लिए हाटस्पाट के रूप में सामने आया है। इसीलिए यहां सबसे अधिक 21 स्थानों पर छापा मारा गया ।।

इन जगहों पर मारे छापे

एक बार त्रिपुरा में घुसपैठ कराने के बाद उन्हें असम, पश्चिम बंगाल होते हुए विभिन्न राज्यों में भेजा जाता था। कुछ घुसपैठियों को असम और पश्चिम बंगाल में ही बसाने की बात भी सामने आई है। त्रिपुरा के अलावा कर्नाटक में 10, असम में पांच, पश्चिम बंगाल में तीन, तमिलनाडु में दो और पुडुचेरी, तेलंगाना व हरियाणा में एक-एक स्थान पर छापा मारा गया।

कोरोना के दौरान रद्द उड़ानों के पैसे इसी महीने लौटाने होंगे, एजेंसियों पर केंद्र सरकार ने शुरू की सख्ती

- कंपनियों को तुरंत पैसा वापस करने का निर्देश
- सुप्रीम कोर्ट ने पैसे लौटाने का निर्देश दिया था

कोविड के दौरान रद्द उड़ानों के पैसे नहीं लौटाने वाली एजेंसियों पर केंद्र सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बुधवार को उपभोक्ता हित को प्रभावित करने वाले ऑनलाइन ट्रैवल संचालकों (एग्रीगेटर्स) के साथ बैठक की और उन्हें नवंबर के तीसरे हफ्ते तक लंबित रिफंड का भुगतान करने का निर्देश दिया। शिकायतों के समाधान के लिए एयरलाइंस के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन मिलकर काम करेगा।

नई दिल्ली। कोविड के दौरान रद्द उड़ानों के पैसे नहीं लौटाने वाली एजेंसियों पर केंद्र सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बुधवार को उपभोक्ता हित को प्रभावित करने वाले ऑनलाइन ट्रैवल संचालकों (एग्रीगेटर्स) के साथ बैठक की और उन्हें नवंबर के तीसरे हफ्ते तक लंबित रिफंड का भुगतान करने का निर्देश दिया।

शिकायतों के समाधान के लिए एयरलाइंस के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन मिलकर काम करेगा। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में मेक-माईट्रिप, यात्रा और क्लियर ट्रिप आदि प्रमुख एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ कुछ सक्रिय उपभोक्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान विभाग की विशेष सचिव और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) प्रमुख निधि खरे ने एक प्रस्तुति के जरिए ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफार्मों पर प्रचलित 'डार्क पैटर्न' के बारे में बताया।

इन कंपनियों को नोटिस जारी

सीसीपीए ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफार्मों ईज माई ट्रिप, यात्रा, मेक माई ट्रिप, हैप्पी ईजी गो, क्लियर ट्रिप के साथ ट्रैवल एजेंसियों थॉमस कुक और केसरी टूर्स को नोटिस जारी किया है। वीणा वर्ल्ड, नीम हॉलीडेज और मैंगो हॉलीडेज को उपभोक्ताओं को तुरंत पैसा वापस करने का निर्देश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पैसे लौटाने का निर्देश दिया था

सीसीपीए के हस्तक्षेप और प्रयासों से इक्सिगो और थामस कुक नाम की दो कंपनियों ने उपभोक्ताओं को पूरी राशि सफलतापूर्वक वापस कर दी है। बैठक में लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों के पैसे नहीं लौटाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के तीन साल पहले के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा गया कि बहुत सारी शिकायतें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) पर अभी भी लंबित हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सारे पैसे लौटाने का निर्देश दिया था।

सांगानेर के सैकड़ो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की

परिवहन विशेष-अनूप कुमार शर्मा भीलवाड़ा

भीलवाड़ा। सांगानेर से सैकड़ो कार्यकर्ता आज कांग्रेस छोड भाजपा में सम्मिलित हुए भाजपा जिला कार्यालय में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ,भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया, भाजपाजिला अध्यक्षप्रशांत मेवाड़ा, भीलवाड़ा विधानसभा भाजपा प्रत्याशी विट्ठल शंकर अवस्थी,के सानिध्य में गोपाल कीर के साथ सैकड़ो कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में बड़े उत्साह के साथ सम्मिलित हुए, इस अवसर पर जिला कार्यालय में समारोह आयोजितकियागयाजिसमेंजनसंघ के वयोवृद्धनेताएवंपूर्वभाजपापार्षद भंवरलाल कोठारी, सुरेश पारीक, जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद त्रिपाठी, गोपाल तेली, कुलदीप शर्मा मुकेश शर्मा, सरपंचसंघ अध्यक्षशक्तिसिंह कालियास , सुभाष मंडल अध्यक्ष मनीषपालीवाल, अविनाशजीनगर उपस्थित थे हरियाणा पूर्व प्रदेश अध्यक्षबराला नेकहां की कार्यकर्ता भाजपा विचारधारा एवं मोदी के कार्यों के साथ है। सांगानेर के सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश से 21 किलो का फूलों का हार जनप्रतिनिधियों ,पदाधिकारीयो को पहनाया, उनका तिलक लगाकर स्वागतकियागया।

एक महीने में दो हिट एंड रन हैं: एक में पुलिस सक्रियता, दूसरे में दबाव?

मनोरंजन सासमल , ओड़िशा

भुबनेस्वर : ओड़िशा की राजधानी में अराजकता और बढ़ते अपराध पर नियंत्रण के लिए जिम्मेदार कमिश्नरेट पुलिस को लेकर राजधानी से लेकर झारसुगुड़ा तक चर्चा है. राजधानी में एक महीने के भीतर कुछ हिट-एंड-रन मामले हुए, लेकिन जिस तरह से पुलिस उनकी जांच कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि पुलिस बड़े लोगों पर शिकंजा कसने से डर रही है और आम आदमी के न्याय की अनदेखी करें.

महीने के अंत में राजमहल चौक के यहाँ एक सेपचैम्बर हुआ। जिसमें एक मजदूर की कार के पहिये के नीचे कुचलकर मौत हो गई. दूसरी घटना अक्टूबर के अंत में हुई जब बिधायिका दीपाली दास के भाई की कंपनी की रेंज रोवर कार ने पावर हाउस स्ट्रीट पर एक बाइक को टक्कर मार दी। जिसमें एक युवती की मौत हो गई जबकि दूसरी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है.

30 सितंबर की देर रात राजमहल स्ट्रीट पर हुए हादसे में पुलिस ने 3 अक्टूबर को फरारी कार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी का पता जांचा और उसे गिरफ्तार कर लिया.

लेकिन 31 अक्टूबर को पावर हाउस स्ट्रीट पर हुए हादसे में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया. कार का ड्राइवर कौन है. दुर्घटना का कारण बनी कार की अगली सीट पर लगे दोनों गुब्बारे हादसे के बाद फूट जाने से यह सवाल खड़ा हो गया है कि गाड़ी में और कौन था, जबकि पुलिस इस पहलू पर चुप है।

वहीं, कमिश्नरेट पुलिस मुख्यालय दुर्घटनास्थल से 50 मीटर की दूरी पर है. यह दिल दहलाने वाली बात है कि इस मामले में सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक नहीं होने पर पुलिस बड़े आदमी पर हाथ डालने से कतरा रही है, जबकि पुलिस सभी मामलों में दोषी मानने तक पहुंच गई है और सीसीटीवी सिस्टम के ठीक से काम करने का सबूत दे रही है।

झारसुगुड़ा बीजेडी विद्यायिका दीपाली दास और उनके भाई इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं. हादसे के बाद से वह सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। दूसरी ओर, राजनीतिक दल दावा कर रहे हैं कि कार के अंदर पूर्वतन मंत्री नब दास का बेटा विशाल दास था. हादसे के बाद पुलिस उसे लेकर चली गई।

मामले को और भी बदतर बनाने के लिए, राजधानी में मोबाइल चोरी और डकैती के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने और मुकदमे में भेजने के दौरान पुलिस आयुक्त सौमेंद्र प्रियधार्थी की चुप्पी और डीसीपी प्रतीक सिंह की चुप्पी, यह कहना पूरी तरह से गलत होगा कि पुलिस का काम अच्छा चल रहा है.

इस मामले में जाजपुर जिले बरी के लोपामुड़ा साहू की दुर्घटना के तीन दिन बाद मौत हो गयी. इसी प्रकार एक और गंभीर कान्हू चरण नायक गंभीर रूप से जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। लेकिन करोड़ों रुपये के मालिक विशाल दास या राज्य सरकार की ओर से कोई सहानुभूति नहीं दिखायी गयी.

भाजपा का जनसंपर्क अभियान शहर में जोरों पर

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। विधानसभा भाजपा प्रत्याशी विट्ठल शंकर अवस्थी का जनसंपर्क कार्यक्रम का आज शुभारंभ बापू नगर सी सेक्टर से प्रारंभ हुआ, जिसमें मंडल अध्यक्ष अनिल सिंह जादौन पूर्व मंडल अध्यक्ष विमल जैन एवं पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष प्रेमजी बिश्नोई ,पार्षद राम सिंह शक्तावत, लव कुमार जोशी, इंदु टाक ,पंडित अशोक शर्मा, मंडल महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती मधुबाला अग्रवाल, वरिष्ठ कार्यकर्ता उदय सिंह भाटी, राजू वैष्णव राजेंद्र सिंह, दशरथ सिंह , हरीश मानवानी, अमित शर्मा रतन अग्रवाल एवं सभी बूथ अध्यक्ष उपस्थित हुए, कार्यक्रम का समापन वरिष्ठ कार्यकर्ता ओम व्यास के निवास पर हुआ अवस्थी जैन मुनि के पीच्छीका परिवर्तन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए

विद्यासागर वाटिका में जैन दिगंबर संत मुनि आदित्य सागर जी महाराज के पिच्छिका परिवर्तन कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी विट्ठल शंकर अवस्थी सम्मिलित हुए, महाराज श्री के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया।

चारभुजा नाथ के 10 अवतार सोने चांदी जड़ित दर्शन होंगे धनतेरस से दीपावली तक

अंन्नकूट महोत्सव मनेगा 13 को

परिवहन विशेष-अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। श्री माहेश्वरी समाज श्री चारभुजा जी मंदिर ट्रस्ट के बडा मंदिर में चारभुजा नाथ के 10 अवतार भी अब स्वर्ण एवं चांदी जड़ित दर्शन देंगे तीन दिवसीय विशेष दर्शन में धनतेरस को प्रातः 9 बजे से दीपावली को रात्रि तक चारभुजा नाथ के स्वर्ण दर्शनों का आकर्षण केंद्र रहेगा त्योहारों को देखते हुए पूरे मंदिर पर आकर्षक रंग-बिरंगे बल्बों से विद्युत सज्जा भी करवाई गई

ट्रस्ट मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि ट्रस्ट अध्यक्ष उदयलाल समदानी ट्रस्ट मंत्री छीतरमल डाड, रामेश्वर तोषनीवाल,चंद्र सिंह तोषनीवाल, सत्यनारायण सोमानी, बालमुकुंद राठी बद्रीलाल डाड आदि की देखरेख में ट्रस्ट द्वारा तैयार 1 किलो 813 ग्राम स्वर्ण चांदी जड़ित पहली बार 10 अवतार को भी बनवाया गया है जिसे दीपावली के पावन अवसर पर 10 अवतार को स्वर्ण पोशाक धारण करायी जाएगी इससे पहले चारभुजा नाथ की मूल प्रतिमा के लगभग 3 किलो स्वर्ण चांदी जड़ित विशेष पोशाक बनाई गई उसे भी इस दौरान चारभुजा नाथ को धारण कराया जाएगा चारभुजा नाथ की पूरी मूर्ति की पोशाक एवं 10 अवतार के नए बनाए गए स्वर्ण चांदी जड़ित पोशाक एवं उनके नीचे गायों सहित 7.800 ग्राम स्वर्ण चांदी से जडित चारभुजा नाथ का दरबार भक्तों के लिए तीन दिवसीय दर्शनों हेतु दमकेगा,

बड़े मंदिर में चारभुजा नाथ के लगभग 3 फीट की चमत्कारिक आकर्षक प्रतिमा है जिसके चारों ओर 10 विष्णु अवतार के विशेष आकर्षण कृतियों के दर्शन है जिसे अभी हाल ही में ट्रस्ट द्वारा स्वर्ण जडित करवाया गया है।

अन्नकूट महोत्सव 13 को मनाया जाएगा

श्री माहेश्वरी समाज श्री चारभुजा जी मंदिर ट्रस्ट के बडा मंदिर में अन्नकूट महोत्सव की धूम 13 नवंबर को अन्नकूट के अवसर पर होगी इस दिन चारभुजा नाथ विशेष श्रृंगार में रहेंगे 6 बजे महा आरती होगी अन्नकूट के विशेष प्रसाद में चावल ,चवला, विभिन्न तरह की सब्जियां, मिठाईयो का भोग लगाया जाएगा तत्पश्चात प्रसाद वितरण किया जाएगा

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023